



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2007/भाद्र 26, 1929

No. 273]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2007/BHADRA 26, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2007

अंतिम जांच परिणाम

**विषय:** स्विट्जरलैंड तथा चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

**सं. 14/11/2005-डीजीएडी.**—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. जबाके मैसर्स निकोलस पीरामल इंडिया लि., (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने अधिनियम और उसकी नियमावली के अनुसार स्विट्जरलैंड तथा चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन की पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए दिनांक 23 मार्च, 2006 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई ।

3. प्राधिकारी ने दिनांक 20 फरवरी, 2007 के अपने प्रारंभिक जांच परिणामों के जरिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी और प्राधिकारी की इन सिफारिशों पर कार्य करते हुए राजस्व विभाग ने दिनांक 28 मार्च, 2007 की अपनी अधिसूचना सं० 47/2007-सीमाशुल्क के जरिए संबद्ध वस्तु पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

4. प्राधिकारी द्वारा उक्त जांच की शुरुआत करने संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी करने के पश्चात् इस जांच के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।
  - (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को 20 फरवरी, 2007 के प्रारंभिक जांच परिणाम की एक प्रति भेजी और प्रारंभिक जांच परिणामों पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों आमंत्रित कीं। जांच के पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणाम की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
  - (ii) प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रतिक्रिया में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों को रिकार्ड में रखा गया है और प्राधिकारी ने उनमें उठाए गए मुद्दों की इस प्रकटन विवरण में जांच की है।
  - (iii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपान्तर उसके द्वारा रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।
  - (iv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए पी पी) के आधार पर उत्पादन की ईष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकाली गयी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति की समाप्ति के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा।
  - (v) प्राधिकारी ने समस्त हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 09.04.2007 को सार्वजनिक सुनवाई की। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा किए गए मौखिक अभ्यावेदनों को लिखित में पुनः प्रस्तुत किया गया था और उसे इस जांच के प्रयोजनार्थ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
  - (vi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में उनके गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। वह सूचना जिसकी प्रकृति गोपनीय है अथवा जिसे इसके अगोपनीय सारांश के साथ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसे गोपनीय माना गया है। इस जांच में \*\*\* चिह्न घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत इसे गोपनीय माना गया है।
  - (vii) इन जांच परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्यों और निर्धारण के आधार को दिनांक 24 अगस्त, 2007 के पत्र में सामान्य प्रकटन और शामिल पक्षकारों के गोपनीय प्रकटनों द्वारा ज्ञात निर्यातकों को बताया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन के उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों पर उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक ये विभिन्न पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क एवं दावे इनके साक्ष्यों एवं आंकड़ों से परिपुष्ट होते हैं।
  - (viii) जांच 1.4.2004 से शुरू होकर 30.9.2005 (जांच अवधि) तक की अवधि में की गई थी।
  - (ix) संक्षिप्तता की दृष्टि से विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व मुद्दों जिनपर प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले ही संभव सीमा तक विचार किया गया है, को दोहराया नहीं गया है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

5. जैसा कि प्रारंभिक जाँच परिणामों में दर्ज किया गया है, वर्तमान जाँच में शामिल उत्पाद विटामिन ए पामिटेट है। विटामिन ए पामिटेट का विनिर्माण विभिन्न सांद्रताओं और रूपों में किया जाता है और इन ग्रेडों की तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के कारण विटामिन ए की सभी सांद्रताओं और रूपों को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया था। तथापि, संबद्ध देशों के उत्तरदाता निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कुछेक मुद्दे उठाए हैं जिनकी निम्नानुसार जाँच की गई है:-

### ग.1 निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. प्रारंभिक जाँच परिणाम के बाद की अपनी टिप्पणियों में चीन के निर्यातकों ने निवेदन किया है कि संबंधित उत्पादों के दायरे को परिभाषित करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मानदण्ड के रूप में केवल समग्र उत्पाद का प्रयोग किया है और उत्पादों/ग्रेडों/प्रयोगों एवं बाजार खण्डों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरों को ध्यान में नहीं रखा है। अतः प्राधिकारी को उन उत्पादों/ग्रेडों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें जाँच अवधि के दौरान किसी क्षतिकारक पाटन का सामना नहीं करना पड़ा है और जाँच के दायरे को सीमित कर देना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि जाँच अवधि के दौरान विटामिन ए पामिटेट 1.0 एम आई यू/जी एम का आयात नहीं किया गया है और ग्रेड 1.7 तथा ग्रेड 1.0 वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक किस्म की माँग अंतिम प्रयोक्ता की अपेक्षाओं, अधिमानों तथा सुविधा और सेवा प्रदान किए जा रहे बाजार खण्ड एवं वितरण पैल पर निर्भर करती है। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू वस्तुओं और चीन के उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा निर्यातित वस्तुओं के बीच व्यापार के स्तरों में बहुत अधिक भिन्नता है और उनके बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। घरेलू उद्योग की वेबसाइट सूचना का उल्लेख करते हुए निर्यातकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से केवल ग्रेड 1.7 के 9 अलग-अलग उत्पादों/रूपों का उत्पादन करता है और संबद्ध वस्तु के विभिन्न ग्रेडों/रूपों के प्रयोक्ता, बाजार खण्ड तथा खपत के पैटर्न अलग-अलग हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं चीन से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट के विभिन्न रूप एवं सांद्रताएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और इसलिए उन्हें विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

7. स्विटजरलैंड के निर्यातकों ने अपने अभ्यावेदनों में निवेदन किया है कि जाँच अवधि में स्विटजरलैंड से विटामिन ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/जी एम के अलावा किसी अन्य उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया है। अतः, अन्य सभी विटामिन ए उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना अपेक्षित है।

### ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

8. घरेलू उद्योग ने अपने अभ्यावेदनों में तर्क दिया है कि "विटामिन ए पामिटेट" विभिन्न सांद्रताओं अर्थात् विटामिन ए पामिटेट 1.7 और विटामिन ए पामिटेट 1.0 में उपलब्ध है। चूँकि विटामिन ए पामिटेट की विभिन्न सांद्रताओं का अंतिम उपयोग एक ही है इसलिए वर्तमान जाँच में संबद्ध वस्तु की सभी सांद्रताओं और रूपों को शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि, वर्तमान में संबद्ध

वस्तु की केवल 1.7 एम आई यू/जी एम सांद्रता का आयात किया जाता है, तथापि आयातों से 1.7 एम आई यू/जी एम और 1.0 एम आई यू/जी एम दोनों की बिक्री प्रभावित होती है क्योंकि प्रयोक्ता द्वारा इन दोनों ग्रेडों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि उच्चतर सांद्रता की कम कीमत पर उपलब्धता से कम सांद्रता की प्रति इकाई कीमत में आनुपातिक रूप से कमी होती है और प्रयोक्ता अपनी लागत को कम करने के लिए उच्चतर सांद्रता को खरीदने की तरजीह देते हैं। अतः प्राधिकारी को एम आई यू/जी आधार पर विटामिन ए पामिटेड पर पाटनरोधी शुल्क लगाने पर भी विचार करना चाहिए जिसे संबद्ध वस्तु की अधिक या कम सांद्रता के आधार पर आनुपातिक रूप से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ई यू, सिंगापुर और जॉर्जिया के मूल की अथवा वहाँ से आयातित संबद्ध वस्तु की जाँच में ऐसा किया गया था। अतः इस मुद्दे का समाधान किया जा चुका है और अंतिम जाँच परिणाम तथा उसके बाद की मध्यावधि समीक्षा जाँच में इस प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

9. प्रश्नगत ग्रेडों के प्रयोगों के मुद्दे पर घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य रूप से खाद्य एवं फार्मा उत्पादों के रूप में मानव पोषण (यूनीसेफ कार्यक्रम सहित) के साथ सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में कुछ उपयोगों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक खाद्य ग्रेड का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया है कि विटामिन ए पामिटेड 1.6 खाद्य ग्रेड है जिसका प्रयोग पशु उपभोग के लिए होता है और उसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया गया है।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

10. विभिन्न विनिर्माताओं की तकनीकी पुस्तिकाओं से यह संकेत मिलता है कि विटामिन ए पामिटेड एक नारंगी पीला से पीलापन लिए लाल तैलीय द्रव है जो 20 डिग्री से कम तापमान पर दानेदार हो जाता है। इसमें विटामिन ए पामिटेड और विटामिन ए एसिटेड होता है जिसमें से विटामिन ए पामिटेड की मात्रा कम से कम 90 प्रतिशत और विटामिन ए एसिटेड की मात्रा 10 प्रतिशत से अनधिक होती है। विटामिन ए एसिटेड की उपस्थिति विनिर्माण की रसायनिक प्रक्रिया कारण होती है। इसमें एण्टी ऑक्सीडेंट के रूप में बी एच ए तथा बी एच टी होते हैं। विटामिन ए पामिटेड का उत्पादन विभिन्न सांद्रताओं/शक्तियों में विशेष रूप से 1.7 एम आई यू/जी एम और 1.0 एम आई यू/जी एम में किया जाता है, जिनका उपयोग भेषज, सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य अनुपूरक अनुप्रयोगों में किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विटामिन ए पामिटेड ग्रेड 1.6 एक खाद्य ग्रेड है जिसका उपयोग पशु उपभोग हेतु होता है और उसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया गया है।

11. निर्यातकों के अभ्यावेदनों से यह भी संकेत मिलता है कि 1.7 एम आई यू/जी एम हरापन लिए पीला से सुनहरा पीला रंग का तैलीय द्रव है जो भंडारण पर दानेदार हो जाता है। इसमें शुद्ध विटामिन ए पामिटेड होता है। विटामिन ए पामिटेड के अन्य रूपों में बी एच ए/बी एच टी या कुछ मामलों में टोकोफेरॉल एण्टी ऑक्सीडेंट के रूप में होता है। विटामिन ए 1.0 एम आई यू/जी एम भी हरापन लिए पीला से सुनहरा पीला रंग का तैलीय द्रव है जो भंडारण पर दानेदार हो जाता है। इसमें टोकोफेरॉल या बी एच ए/बी एच टी एण्टीऑक्सीडेंट के रूप में होता है। विटामिन ए पामिटेड के इन दोनों प्रकारों में मूलभूत अंतर सांद्रता/शक्ति का होता है। विटामिन ए पामिटेड 1.7 के सभी रूपों की शक्ति एक ही होती है परन्तु उनके वस्तु विवरण का दूसरा भाग एण्टी ऑक्सीडेंट से

संबंधित होता है जो फार्म्यूलेशन (इससे रूप अधिक स्थिर होता है) का हिस्सा होता है। यही 1.0 एम आई यू/जी एम पर भी लागू होता है। सभी रूपों का उपयोग खाद्य, भेषज या सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण में किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया, दोनों उत्पादों के भौतिक एवं रसायनिक विशेषताएँ समान हैं और उत्पाद प्रतिस्थापनीय तथा एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अधिकतम कीमत के निर्धारण के लिए डी पी सी ओ ने विटामिन ए पामिटेड 1.7 और 1.0 को एक ही श्रेणी में रखा है। प्राधिकारी की जानकारी में यह लाया गया है कि सांद्रता के अवमिश्रण में परिवर्तन करके एक-दूसरे के स्थान पर उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है।

12. उपर्युक्त जाँच से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि विटामिन ए पामिटेड की विभिन्न सांद्रताएँ अर्थात् 1.7 एम आई यू/जी एम और 1.0 एम आई यू/जी एम निर्यातकों द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार अलग-अलग उत्पाद होने के बजाय उत्पाद के उप-प्रकार मात्र हैं। ये उत्पाद प्रकार तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। यदि ये दो अलग-अलग उत्पाद होते तो जाँच अवधि के दौरान आयात न किए गए उत्पाद को शामिल न करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का कोई आधार होता। एक विशेष प्रकार (1.7 एम आई यू) का जाँच अवधि के दौरान आयात किया गया है और यदि दूसरे प्रकार को छोड़ते हुए केवल इसी प्रकार पर शुल्क लगाया जाता है तो शामिल न की गई श्रेणी, जिससे शुल्क योग्य वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, का आयात करके शुल्क का आसानी से निवारण किया जा सकेगा। अतः केवल इसलिए कि किसी विशेष समयावधि के दौरान एक उत्पाद उप-प्रकार का आयात नहीं किया गया है, वह उत्पाद विचाराधीन उत्पाद, जिसमें उत्पाद के उन सभी उप प्रकारों को शामिल किया जाता है जो तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, के दायरे से बाहर रखे जाने योग्य नहीं हो जाता है।

13. प्रकटन के पश्चात अपने अभ्यावेदनों में हितबद्ध पक्षकारों ने विटामिन ए पामिटेड 1.0 एम आई यू/जी एम को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इस आधार पर बाहर रखने कि जाँच अवधि के दौरान उसका आयात नहीं किया गया है, के तर्क को दोहराया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सेस्टेट के कुछेक निर्णयों को उद्धृत किया है जिसमें माननीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि कोई वस्तु जिसका भारत को निर्यात नहीं किया गया है, उस पर अधिनियम की धारा 9 क (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

14. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए उपर्युक्त तर्कों को नोट किया है। विचाराधीन वस्तु से समग्र रूप से उत्पाद/वस्तु संदर्भित है न कि उसका कोई उप प्रकार या मॉडल या विनिर्देशन। जैसा कि पहले नोट किया गया है, विटामिन ए पामिटेड 1.7 एम आई यू/जी एम और 1.0 एम आई यू/जी एम उत्पाद के उप प्रकार हैं जिनका अंतिम उपयोग एक है और जिनमें अंतर केवल सांद्रता का है। अतः विटामिन ए पामिटेड 1.7 एम आई यू/जी एम पर शुल्क लगाए जाने का परिणाम विटामिन ए पामिटेड 1.0 एम आई यू/जी एम जिसका अंतिम प्रयोग समान है, के आयात के जरिए शुल्क के निराकरण के रूप में हो सकता है। जबकि विटामिन ए पामिटेड 1.6 एम आई यू/जी एम का अंतिम उपयोग बिल्कुल अलग पशु खाद्य के लिए है और इसलिए वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

15. उपर्युक्त के मदेनजर प्राधिकारी मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को उपयुक्त रूप से विटामिन ए पामिटेट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 1.7 एम आई यू और 1.0 एम आई यू दोनों शामिल हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद में 1.6 एम आई यू शामिल नहीं होगा क्योंकि वह अलग अंतिम उपयोग के साथ अलग उत्पाद है। तदनुसार विचाराधीन उत्पाद को विटामिन ए पामिटेट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें समस्त सांद्रताओं एवं रूपों में विटामिन ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/जी एम तथा विटामिन ए पामिटेट 1.0 एम आई यू/जी एम (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) दोनों शामिल हैं।

16. उत्पाद को उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आई टी सी एच एस वर्गीकरण की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के शीर्ष सं० 293621.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

#### घ. घरेलू उद्योग की स्थिति एवं जाँच की शुरुआत

17. आवेदन मै० निकोलस पीरामल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र ज्ञात उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तु का समग्र उत्पादन करता है। अतः याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को दायर करने का आधार पूरा करता है और वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

#### ड. अन्य अभ्यावेदन तथा उठाए गए मुद्दे:

18. जैसा कि प्रारंभिक जाँच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, आयातक मै. हेक्सागॉन न्यूट्रिशन प्रा. लि. ने अपने निवेदन में तर्क दिया है कि स्विट्जरलैंड ने पिछले तीन वर्षों से 70 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. के अपने कीमत स्तर को बनाए रखा है जबकि चीन ने अपनी 66 अम. डा. की कीमत को घटा कर वर्तमान निर्यात कीमत 56 अम. डॉ. कर दिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि निकोलस पीरामल ने संबद्ध वस्तु का निर्यात उस कीमत से भी कम कीमत पर किया है जिस पर स्विट्जरलैंड से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया गया है।

19. इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया है कि इस उत्पाद की लागत मितव्ययी उपलब्धता अनिवार्य है क्योंकि विटामिन की भारी कमी को पूरा करने के लिए कई धर्मार्थ संगठनों द्वारा विटामिन अनुपूरकों हेतु भारत में परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है। पाटनरोधी शुल्क लागू करने की परिणति एनपीआईएल के लिए एकाधिकार की स्थिति के रूप में होगी और पाटनरोधी शुल्क के कारण उपभोक्ताओं को उच्चतर कीमत का भार वहन करना पड़ेगा।

20. मै. डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स (डीएनपी) ने अपने तर्कों को दोहराया है कि डीएनपी भारतीय बाजार में अपने उत्पाद का पाटन करने की नीति नहीं अपनाती है और याचिकाकर्ताओं को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। यह तर्क दिया गया है कि भारत में और स्विट्जरलैंड में क्रयशक्ति और बाजार संरचना बिल्कुल अलग हैं- जैसाकि प्रति सौदा बेचे गए उत्पादों की मात्रा से स्पष्ट है- जिसका बिक्री कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया है कि ईयू बाजार में की गई बिक्रियाँ भारत को की गई निर्यात बिक्रियों की विशेषताओं से काफी मिलती- जुलती हैं और न कि स्विस् बाजार में की गई बिक्रियों से तथा उन बाजारों में प्राप्त की जा सकने वाली कीमतें भी

तुलनीय हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि स्विट्जरलैंड से आयातित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में वह एकाधिकार पुनः स्थापित हो जाएगा जो सिंगापुर, जार्जिया और ईयू से आयातित उत्पाद पर शुल्क के लागू होने के बाद वर्ष 2003 में और 2004 के पूर्वार्द्ध में याचिकाकर्ता स्थापित करने में सफल रहा था। इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से भारतीय उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत उच्च बिक्री कीमत चुकानी होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी।

### ड.1 गोपनीयता संबंधी मुद्दे

21. मामले के विभिन्न पहलुओं पर अपनी टिप्पणियों के अलावा घरेलू उद्योग और जाँच में भाग लेने वाले निर्यातक दोनों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अत्यधिक गोपनीयता के मुद्दे को उठाया है। जहाँ तक गोपनीयता के मुद्दे और जाँच के पक्षकारों द्वारा सूचना का अपर्याप्त अगोपनीय प्रकटन का संबंध है, उठाए गए मुद्दों की जाँच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संभव एवं व्यवहार्य सीमा तक सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जाँच की गई है और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रकृति के आधार पर गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया गया है। ऐसी सूचना जिसकी प्रकृति गोपनीय है या जिसे अगोपनीय सारांश के साथ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसे गोपनीय माना गया है।

22. प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इस तथ्य के कारण कि इन निर्यातकों ने मानक सेट के रूप में प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, स्विट्जरलैंड तथा चीन जन. गण. के प्रतिभागी निर्यातकों को असहयोगी घोषित किया जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाए। उन्होंने इन पक्षकारों द्वारा अगोपनीय प्रकटनों की अपर्याप्तता के मुद्दे को भी उठाया है।

23. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोग की मात्रा एवं सीमा तथा प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ-साथ अगोपनीय संबंधी मुद्दों की पर्याप्त जाँच की गई है और इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत निवेदनो को स्वीकार किया गया है, हालाँकि इन निर्यातकों द्वारा किए गए कुछेक निवेदनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछेक दावों को अस्वीकार किए जाने या प्राधिकारी द्वारा कुछेक सूचना को स्वीकार न किए जाने से न तो निर्यातक असहयोगी हो जाता है और न ही उस पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का खण्ड लागू होता है।

### च. पाटन एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण

#### च.1. चीन जन. गण.

24. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों में नोट किया था कि पिछले तीन वर्षों में ईयू और अमरीका जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा पाटनरोधी जाँच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। अतः पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) के अनुसार सामान्य मूल्य के अनंतिम आकलन के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया था।

25. पाटनरोधी नियमावली यथासंशोधित के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार व्यक्तिगत व्यवहार हेतु व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा गैर- बाजार अर्थव्यवस्था की पूर्वधारणा का खण्डन तभी किया जा सकता है यदि ऐसे देश के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदण्डों के आधार पर सूचना तथा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें और इसके खण्डन को सिद्ध करें। चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार कर सकें कि क्या :

(क) चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों के कीमत, लागत और कच्ची सामग्री समेत निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री एवं निवेश संबंधी निर्णय पूर्ति तथा माँग को दर्शाने वाले बाजार संकेतकों के प्रतिक्रियास्वरूप लिए जाते हैं और इस संबंध में सरकार का कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतों से पर्याप्त ढंग से बाजार मूल्य प्रदर्शित होते हैं;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था से उत्पन्न महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है;

(ग) ऐसी फर्मों दिवालिया और सम्पत्ति संबंधी कानूनों, जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी देते हैं, के अधीन हैं।

(घ) मुद्रा विनिमय दरों में बाजार दर के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं।

26. चीन में संबद्ध वस्तु के केवल एक विनिर्माता अर्थात् मै0 झेजियांग एन एच यू कं0 लि0 (एन एच यू) तथा उससे संबंधित निर्यातक मै0 सिनकेम इंटरनेशनल कं0 लि0 ने बाजार अर्थव्यवस्था के दृष्टि और व्यक्तिगत व्यवहार का दावा करते हुए निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दिया है। चीन के उत्पादक/निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दावे पर हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

#### च.1.1 घरेलू उद्योग के विचार

27. चीन के निर्यातक के बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावे पर टिप्पणी करते हुए अपने विभिन्न अभ्यावेदनों में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है कि:-

- उनकी अपनी वेबसाइट में प्रकाशित कम्पनी की सूचना के अनुसार कम्पनी की स्थापना पूर्ववर्ती जिनचांग केमिकल कम्पनी के पुनर्गठन के बाद की गई थी जिसकी स्थापना नवम्बर, 1988 में की गई थी और अब यह एक राज्यस्तरीय हाईटेक उद्यम के रूप में विकसित हो चुकी है। ऐसी स्थिति होने के कारण उनके द्वारा यह साबित करना अपेक्षित है कि ऐसे संयंत्र के स्वामित्व को बाजार कीमत के आधार पर निजी पार्टियों को स्थानांतरित कर दिया गया है और यह पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से प्रभावित नहीं था। पैरा 8(3) (ख) में भी प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से



परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और कर्ज की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतानों के संबंध में पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे ले जाई गई अत्यधिक विकृति के अध्यधीन हैं। अतः परिवर्तन की प्रक्रिया और सत्ता की परिसम्पत्तियों और देयताओं का निजीकरण के प्रयोजनार्थ कैसे भूषांकन किया गया है, की जांच करना आवश्यक है। इसलिए निर्यातक का यह तर्क कि प्राधिकारी दर्जे और निजीकरण की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए जांच अवधि से बाहर जांच नहीं कर सकते हैं, तर्कसंगत नहीं है। अतः इसके लिए जांच की आवश्यकता है कि क्या जिस कीमत पर संयंत्र बेचा गया था वह कीमत बाजार के सिद्धांतों के अनुसार है। इसके अलावा उन शेयर धारकों जिन्होंने शेयर घूंजी में निवेश किया था, और किसी भी संबंधित कम्पनी अथवा राज्यों के साथ उनके संबंधों की जांच की जानी भी अपेक्षित है।

- सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्ववर्ती कम्पनी जिनचांग कैमिकल कम्पनी पीआरसी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय टॉर्च प्लान में महत्वपूर्ण नये और हाइटेक उद्यमों में से एक के रूप में अनुमोदित कम्पनियों में से एक कम्पनी रही थी। टॉर्च कार्यक्रम एक राष्ट्रीय योजना है जिसे राज्य परिषदों के अनुमोदन से अगस्त, 1988 में कार्यान्वित किया गया था। इसका उद्देश्य विकासशील हाइटेक उद्योगों के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे हजारों हाइटेक फर्मों और 53 हाइटेक जोनों का पोषण करने और पेटेंट युक्त उत्पादों का विकास करने में भी सहायता की है जो विश्व के उन्नत स्तरों तक पहुँच गए हैं। केन्द्रीय विज्ञान एवं शिक्षा अग्रणी समूह, चूंकि यह मार्च में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में उजागर किया गया था, ने चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक ज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिनव परियोजना को परखने के लिए अगले तीन वर्ष के भीतर 7 बिलियन युआन (843 मिलियन अम0 डॉलर) का निवेश करने का निर्णय लिया था।
- घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में टॉर्च प्लान के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार इसे डब्ल्यूटीओ करार में यथा परिभाषित सब्सिडी कहा जाता है क्योंकि यह सरकारी निकाय द्वारा किया गया एक वित्तीय अंशदान है और इसे जिनचांग कैमिकल कम्पनी जैसी विशिष्ट सत्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। यह तर्क भी दिया गया है कि यद्यपि एससीएम करार के अंतर्गत जहां तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों का संबंध है, चीन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों में अंशदान को उत्पादन लागत और वित्तीय फायदों में शामिल कर लिया गया है जिन्हें कम्पनी को प्रदान किया गया है और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एमईटी के सिद्धांत पूरे किए गए हैं।
- घरेलू उद्योग द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उत्पादक को ब्रांड नेम पालिसी के अंतर्गत समर्थनकारी नीतियां प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है जिसे विशेष रूप से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए 26.1.2005 (जो जांच अवधि के दौरान है) से शुरू करके दो वर्ष के लिए कार्यान्वित किया गया है और इस उत्पादक को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से एक कम्पनी का नाम दिया गया है।
- इसके अलावा उत्पादक ने इस बात का खुलासा भी नहीं किया है कि इसकी यूएस में चीन विटामिन्स एलएलसी के नाम से एक संबद्ध कम्पनी है जो यूएस में न्यू जर्सी में स्थापित है। एमईटी प्रश्नावली में स्पष्ट रूप से अपेक्षित है कि उत्पादक उन कम्पनियों के संबंध में विशिष्ट सूचना दें जो उत्पादक से संबंधित हैं। उत्पादक ने इस सूचना का भी दाखिल किए गए उत्तरों में कहीं खुलासा नहीं किया है।

- प्रकटन के बाद के अपने निवेदनों में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि भारत को किए जाने वाले निर्यात सौदों में शामिल मध्यस्थों के लाभ मार्जिनों आदि में निर्यात कीमत निकालने के लिए पर्याप्त कटौती की जानी चाहिए।

**च.1.2 मै0 झेजियांग एनएचयू कम्पनी लि0 (एनएचयू) चीन पीआर और मै0 सिनचेम इंटरनेशनल कं0 लि0**

28. चीन जन.गण. के निर्यातक ने अपने निवेदनों में इसके बाजार अर्थव्यवस्था दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तर्कों का खंडन किया है। यह दावा किया गया है कि एनएचयू की कोई “यूएस वेबसाइट” नहीं है और इसने अमरीका में एनएचयू या इसकी किसी संबद्ध कम्पनी के संबंध में सूचना देने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया है। एनएचयू ने एमईटी प्रश्नावली के अपने उत्तर में अपनी सभी संबद्ध कम्पनियों का खुलासा किया है।
29. निर्यातक ने अपने निवेदन में तर्क दिया है कि कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने चीन को एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी है और भारत में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी विगत में कई चीनी निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि चाइनीज प्रोटोकॉल ऑफ एक्सेशन टू डब्ल्यूटीओ के अनुबंध 2क2 में चीन ने पारदर्शी रूप से और सद्भाव से उन व्यवसाय क्षेत्रों और यहां तक की कम्पनियों को सूचीबद्ध कर दिया है जो राज्य के नियंत्रण में बनी हुई हैं अथवा सब्सिडी प्राप्त कर रही हैं अथवा जहां सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कीमत के संबंध में निर्णय लेने में भूमिका अदा करती है और जिसमें परिवर्तन अवधि के दौरान सुधार किया जाएगा। यह निवेदन किया गया है कि न तो संबद्ध वस्तुएं उक्त प्रोटोकॉल के उक्त अनुबंध 2क2 में अभिज्ञात की गई हैं और क्योंकि ऐसा व्यवसाय क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में या प्रभावाधीन है और न ही उक्त अनुबंध 2क2 में निर्यातक या उत्पादक का नाम लिया गया है। अतः यह मानने के लिए प्रथम दृष्टया कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि चीन में उक्त संबद्ध वस्तु व्यवसाय क्षेत्र एनएमई के रूप में प्रचालन करता है। अतः यह तर्क दिया गया है कि एनएचयू/सिनचेम को एनएमई शर्तों के अध्याधीन प्रचालन करने वाला नहीं माना जा सकता है और एनएचयू/सिनचेम द्वारा प्रस्तुत सूचना से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि एनएचयू/सिनचेम अपने व्यावसायिक निर्णय बाजार अर्थव्यवस्था में अनन्य रूप से व्यवसाय की विधि से लेते हैं।
30. यह भी निवेदन किया गया है कि हाल के वर्षों में चीन में बनाए गए कानून जो इस व्यवसाय क्षेत्र और एनएचयू/सिनचेम पर लागू होते हैं, बाजार अर्थव्यवस्थाओं में तुलनीय कानूनों के समान हैं और इनको पीओआई तक लागू किया जाना शुरू किया जा चुका था। यह भी तर्क दिया गया है कि एनएचयू का संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार या निर्यातों पर एकाधिकार नहीं है और एनएचयू की कीमत और लागत पर राज्य/सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। एनएचयू कच्चे माल की खरीद करता है और तैयार उत्पादों को बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचता है जिन्हें राज्य/सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि एनएचयू/सिनचेम द्वारा प्रयुक्त लेखांकन प्रणाली किसी बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। एनएचयू/सिनचेम अनुमत वैट प्रतिपूर्ति से इतर कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं करता है जो घरेलू बिक्रियों पर लगाई जाती है और अपनी विदेशी मुद्रा की खरीद अधिकृत डीलर बैंक के जरिए करता है। इसके अलावा उत्पादक की उत्पादन लागतों और वित्तीय स्थिति में कोई विकृति नहीं है जैसाकि गोपनीय उत्तर और उसके साथ संलग्न गोपनीय सूचना से स्पष्ट है। यह तर्क दिया गया है कि उत्पादक ने पूर्व राज्य की परिसम्पत्तियों को परिवर्तित नहीं किया है अथवा उसके मूल्यहास को

विकृत नहीं किया है अथवा वस्तु विनिमय का कर्ज माफी या कर्ज/इक्विटी स्वेप्स में शामिल नहीं किया है या न ही किसी बट्टे खाते का लाभ प्राप्त किया है।

31. यह निवेदन किया गया है कि एनएचयू/सिनचेम दिवालियापन और सम्पत्ति के संबंध में क्रमशः चीन के कानूनों और विनियमों के अधीन है और विनिमय दर सेन्द्रल बैंक द्वारा यथानिर्धारित बाजार दर पर आधारित है। एनएचयू/सिनचेम ने बाजार शर्तों पर बैंकों से उधार लिया है और कार्यसूची के अनुसार अपने ऋणों को लौटाया है।

32. जहां तक राष्ट्रीय टॉय कार्यक्रम का संबंध है, निर्यातक ने तर्क दिया है कि यह कार्यक्रम हाईटेक उत्पादों/प्रक्रिया के विकास और अनुप्रयोग का संवर्धन करने के लिए है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे यदि सबके द्वारा नहीं तो भारत सहित अधिकांश बाजार अर्थव्यवस्था डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, सब्सिडियों और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के भीतर कार्यक्रम ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में छोड़कर एनएचयू को कोई वित्तीय अंशदान और/या लाभ, जो भी हो, स्थानांतरित नहीं किया है।

33. जहां तक पूर्ववर्ती कम्पनियों और होल्डिंग कम्पनियों के इतिहास और पूर्ववृत्त का संबंध है निर्यातक ने तर्क दिया है कि अनुरोध की गई सूचना अनिर्धारित अवधि के लिए नहीं हो सकती है और न तो प्रश्नावली, न ही एनएमई प्रश्नावली, न ही, माननीय प्राधिकारी से एनएचयू/सिनचेम को किसी पत्र में पीओआई और जांच शुरूआत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि से इतर पृथक अवधि निर्धारित की गई है जिसके लिए सूचना मांगी गई है। यह तर्क दिया गया है कि एनएमई प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न में सहयोगी पार्टी के “इतिहास” हेतु अनुरोध किया गया है। इसी तरह उक्त नियमावली की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ (3) में दिए गए बाजार अर्थव्यवस्था के चार मानदंडों में से किसी भी मानदंड में असीमित “इतिहास” का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः 10-15 वर्ष पहले प्रतिवादी के पूर्ववृत्त या “इतिहास” की कानूनी स्थिति के आधार पर एनएचयू की घरेलू बिक्री के कीमत ढांचे और पीओआई के दौरान भारत को सिनचेम के निर्यात के संबंध में निष्कर्ष निकालना अनुचित और अतार्किक है। जिसका कीमतों के सामान्य मूल्य और/अथवा तुलनीयता पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। एनएचयू के शेयर धारकों पर इस जांच में उत्तर देने की जिम्मेदारी थोपना भी अनुचित और अतार्किक है।

### च.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है। मै0 झिजियांग एनएचयू कम्पनी लि0 (एनएचयू) चीन, जन.गण. ने मै0 सिनचेम इंटरनेशनल कं0 लि0 के साथ निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। एनएचयू चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और अपनी संबद्ध कम्पनी सिनचेम जो एक व्यापार कम्पनी है, के जरिए इनका भारत को निर्यात करता है। एनएचयू ने दावा किया है कि यह चीन में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एक कम्पनी है और इसके शेयरों का बड़ा हिस्सा मै0 जिनचांग काऊंटी सिंथेटिक कैमिकल फैक्ट्री (जिनचांग) नाम एक होल्डिंग कम्पनी के पास है और इसके एक हिस्से को सार्वजनिक शेयर धारकों द्वारा निवेश किया जाता है। कम्पनी के प्रश्नावली उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था उत्तर की जांच की गई थी और एनएचयू और सिनचेम के परिसर में मौके पर जांच और सत्यापन किया गया था।

35. मै0 झिजियांग एनएचयू कं0 की स्थापना चीनी कम्पनी लॉ के अंतर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में वर्ष 1998 में की गई थी। प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए उत्तर देने वाली चीनी कम्पनियों

के पूर्ववृत्त की जांच की थी कि क्या उत्पादक की लागत और कीमतों पर राज्य के हस्तक्षेप अथवा पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से विकृतियों को आगे ले जाने से अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सत्यापन से पता चलता कि एनएचयू की उत्पादन इकाई पूर्व में जिनचांग काऊंटी सिंथेटिक कैमिकल फैक्ट्री के स्वामित्व में थी। इस फैक्ट्री की स्थापना चीनी उद्यम कानून के संक्रमण चरण में प्रचलित सामूहिक उद्यम प्रणाली के अंतर्गत सामूहिक स्वामित्व उद्यम के रूप में वर्ष 1989 में की गई थी। तथापि, सत्यापन से पता चला कि प्रारंभ में उद्यम में जिनचांग देश के कतिपय स्कूलों और स्कूल शिक्षकों द्वारा निवेश किया गया था। वर्ष 1994 में उद्यम को चीन के नये कम्पनी कानून के अंतर्गत “सामूहिक स्वामित्व के निगम” के रूप में निगमित किया गया था।

36. झिजियांग एनएचयू जो इस मामले में प्रतिवादी उत्पादक कम्पनी है, की स्थापना वर्ष 1998 में जिनचांग कैमिकल्स फैक्ट्री की प्रमुख शेयर धारिता के साथ सीमित शेयरों द्वारा एक नई लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई थी और इसने झिजियांग प्रांतीय सरकार का वर्ष 1999 में अनुमोदन प्राप्त किया था। मै0 जिनचांग सिंथेटिक कैमिकल्स फैक्ट्री की उत्पादन इकाई का इस यूनिट को स्थानांतरण एनएचयू में जिनचांग के पूंजीगत अंशदान के रूप में किया गया था।

37. मै0 जिनचांग सिंथेटिक कैमिकल फैक्ट्री की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन मै0 जिनचांग एसेट्स एप्रेजल कंपनी द्वारा वर्ष 1998 में किया गया था और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस मूल्यांकन का प्रयोजन शेयरों द्वारा एक लिमिटेड कंपनी की स्थापना करना था। मूल्यांकन भूमि को छोड़कर कंपनी की समूची परिसम्पत्तियों के लिए किया गया था। जिनचांग सिंथेटिक की सभी निवल परिसम्पत्तियों का पूर्ववर्ती द्वारा कंपनी के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में एन एच यू में निवेश किया गया था। तथापि, भूमि और भवन के रूप में जिनचांग की स्थिर परिसम्पत्तियों को नई सत्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया है और यह नई कंपनी की पूंजी का हिस्सा नहीं है। एन एच यू आम जनता को साधारण शेयर जारी करके वर्ष 2004 में सार्वजनिक लि0 कंपनी बनी थी। तथापि, मूल प्रवर्तक उद्यम अर्थात् जिनचांग इस कंपनी का प्रमुख शेयर धारक है। एन एच यू के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री हू बेफेन हैं जो जिनचांग का मुख्य प्रवर्तक हैं और अन्य प्रवर्तक बोर्ड में निदेशक हैं।

38. सत्यापन के दौरान कंपनी द्वारा राष्ट्रीय टॉर्च कार्यक्रम और ब्रांड संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में कतिपय मुद्दों की जांच भी की गई थी। चीन जन.गण. की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ एक प्रश्नावली भी भेजी गई थी कि वे इन कार्यक्रमों और इस मामले में प्रतिवादी कंपनी द्वारा प्राप्त फायदों, यदि कोई हो, के संबंध में कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराएं। चीन के अधिकारियों के साथ एम ओ एफ सी ओ एम में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। एम ओ एफ सी ओ एम ने उक्त प्रश्नावली का एक लिखित उत्तर भी दाखिल किया है। एम ओ एफ सी ओ एम ने निवेदन किया है कि सब्सिडी संबंधी मुद्दे बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे हेतु प्रासंगिक मानक नहीं हैं। तथापि, इन कार्यक्रमों और कंपनी को होने वाले लाभों की यह पता लगाने के लिए जांच की गई है कि क्या इन कार्यक्रमों का संबंधित निर्यातक के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतों पर अत्यधिक विकृतिकारी प्रभाव पड़ा है।

39. सत्यापन की प्रक्रिया और चीन के अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान यह खुलासा किया गया था कि स्थानीय आर्थिक विकास को सुकर बनाने के लिए हाइटेक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय टॉर्च कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष

1998 में गैर-बाध्यकारी कार्यक्रम के रूप में की गई थी। सरकारी एजेंसियों के विभिन्न स्तरों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोगों ने कार्यक्रम को लागू किया था। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत संबद्ध उत्पाद विटामिन को शामिल किया गया था। सत्यापन के दौरान कंपनी ने इस बात की पुष्टि की थी कि वे उक्त कार्यक्रम के लाभानुभोगी हैं और उन्होंने जुलाई, 2002 के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय टॉर्च कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिससे पता चलता है कि इस उत्पाद हेतु समूचा निवेश स्व-वित्त पोषित है। कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कंपनी ने एन एच यू संग्रह में समूची परियोजना कार्यान्वित की थी और उन्हें हाइटेक औद्योगिक विकास क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत कोई अंशदान नहीं मिला है। अतः उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की ओर से इस कंपनी को कोई अंशदान नहीं दिया गया है।

40. इस नीति के नीतिगत दस्तावेजों से पता चलता है कि इस नीति के अंतर्गत शामिल उत्पादों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं :

- (क) उत्पादों हेतु बैंकों से निधियां प्राप्त करने के लिए सरकारी सहायता; निधियों तथा प्राथमिकता के आधार पर ऋण;
- (ख) राज्य से भी निधि की सहायता;
- (ग) कम ब्याज दरों पर ऋण को सुकर बनाना;
- (घ) लाभानुभोगियों को चीन के निर्माण बैंक से विशेष ग्रेड ऋण के लिए हकदार बनाना।

वर्ष 2003 के लिए कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक अभिकरण की वार्षिक रिपोर्ट के प्रारंभिक सार कंपनी द्वारा यह दावा करने के लिए प्रस्तुत किए कि कार्यक्रम के सब्सिडी घटक नगण्य थे। नेशनल टॉर्च प्रोग्राम 2003 की वार्षिक रिपोर्ट जिसकी एक प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई थी, दर्शाती है कि इस कार्यक्रम के तहत कुल बैंक ऋण सभी परियोजनाओं के लिए 18.49 बिलियन आर एम बी था तथा सब्सिडी तत्व के लिए 36 हाई टेक परियोजनाओं के लिए 1.85 बिलियन आर एम बी था। निर्यातक ने अपनी टिप्पणियों में यह प्रस्तुत किया है कि ये 36 हाई टेक परियोजनाएं विशिष्ट उत्पादों की तुलना में 36 हाई टेक विकास क्षेत्र हैं और बैंक ऋण वाणिज्यिक शर्तों पर लिए गए हैं। तथापि, पूर्व में वर्णित नीतिगत दस्तावेज इस दलील की पुष्टि नहीं करते।

41. जहाँ तक ब्रांड संवर्धन कार्यक्रम का संबंध है, यह कार्यक्रम चीन जन.गण. की सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सुधार एवं विकास समिति, वित्त मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एम ओ एफ सी ओ एम द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कार्यक्रम के उद्देश्य ब्रांड उन्मुख दृष्टिकोण हेतु उद्यमों को मार्गदर्शन देना, गुणवत्ता नियंत्रण और आर एंड डी को सुदृढ़ करना, उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि करना आदि मुख्यतः नकली उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने पर लक्षित थे। कंपनी ने यह पुष्टि की थी कि उन्होंने समग्र रूप से कंपनी के लिए न कि किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए इस स्कीम के अंतर्गत आर एंड डी विकास हेतु वर्ष 2005 में \*\*\* आर एम बी का एकमुश्त अनुदान प्राप्त किया था।

42. जहाँ तक सिनकेम अर्थात् एन एच यू से संबंधित निर्यातक की स्थिति का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिनकेम, झिनचांग सिंथेटिक केमिकल फैक्ट्री जो एन एच यू की प्रमुख अंशधारक भी है; तथा एक वैयक्तिक उद्यमी श्री वू टियपिंग द्वारा निवेश के माध्यम से 1998 में स्थापित एक निजी सीमित उत्तरदायी कंपनी है। इसलिए, उत्पादक कंपनी (एन एच यू) और व्यापारिक कंपनी (सिनकेम) दोनों संबंधित हैं और उनकी प्रमुख अंशधारक सत्ता में झिनचांग

सिंथेटिक केमिकल फैक्ट्री द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और उनकी वही हैसियत होगी जैसी कि मुख्य धारक कंपनी (झिनचांग) की है। आधार रूप में यह डालियन के बांडेड जोन में 2001 के पहले बांडेड जोन में स्थापित उद्यमों को उपलब्ध विभेदकारी कर लाभ प्राप्त करने हेतु स्थापित व्यापारिक कंपनी है। तथापि, यह कंपनी मुख्यतः एन एच यू की बाह्य शाखा के रूप में आर्डर प्राप्त करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करती है जबकि वास्तविक निर्यात दस्तावेजी कार्य आदि एन एच यू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंपनी के नाम से किये जाते हैं जिसके पास उत्पाद हेतु निर्यात लाइसेंस है और चीनी कानून के तहत वैट प्रतिअदायगी लाभ हेतु अर्हता है।

43. उत्पादक कंपनी मै0 एन एच यू ने प्रमुख कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी आपूर्तिकर्ताओं की सूची उपलब्ध कराई थी और यह दावा किया था कि कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता निजी सत्ताएं हैं और उनसे संबंधित नहीं है। कच्ची सामग्री और यूटिलिटीज के आपूर्तिकर्ताओं की सूची काफी लम्बी है और इन आपूर्तिकर्ताओं के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना संभव नहीं था। जहाँ तक विद्युत का संबंध है इसकी खरीद राज्य विद्युत उत्पादकों से की गई थी।

44. उपर्युक्त जांच से यह पता चलता है कि एन एच यू के प्रमुख शेयरधारक अर्थात् मै0 जिन्चेंग सिंथेटिक केमिकल फैक्ट्री के स्वामित्व का दर्जा नियंत्रक कंपनी में उनके द्वारा किए गए निवेशों और स्कूलों के भागीदारी के कारण संदेहास्पद बना रहा है। अतः एन एच यू के नियंत्रणकारी स्वामित्व और स्कूलों के जरिए पूंजी निवेश के रूप में राज्य की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन्चेंग से एन एच यू की परिसंपत्तियों और देनदारियों का नई सत्ताओं में अंतरण पारदर्शी नहीं है और उससे सही बाजार मूल्य प्रदर्शित नहीं होता है। नियंत्रक कंपनी द्वारा अंतरित परिसम्पत्तियों में भूमि एवं भवन भी शामिल नहीं है और ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य को एन एच यू की पूंजीगत परिसम्पत्तियों में हिसाब में नहीं लिया गया है। जहाँ तक एन एच यू को सरकार की वित्तीय तथा अवसंरचनात्मक सहायता तथा सरकार के राष्ट्रीय टार्च कार्यक्रम तथा ब्राण्ड नीति के जरिए शामिल उत्पाद का संबंध है, कंपनी को जाहिर तौर पर सीमित रूप में इन कार्यक्रमों का लाभ मिला है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि यह सब्सिडी जांच नहीं है तथापि कंपनी की लागत और कीमतों पर ऐसी सहायता का सामान्य मूल्य के निर्धारण पर प्रभाव पड़ेगा।

45. चीन के उत्पादक/निर्यातक ने प्रकटन संबंधी अनुरोधों के बाद अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि यद्यपि प्राधिकारी एन एच यू के रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत साक्ष्य और छिटपुट सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में कुछेक मुद्दे पाते हैं तथापि ऐसे मुद्दों से पर्याप्त बिक्री की पुष्टि करने के लिए "पर्याप्तता" संबंधी जांच पूरी नहीं हो सकती है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती गैर बाजार प्रणाली से विकृतियों को आगे लाने के मुद्दे का पूर्वोक्त पैराग्राफों में पर्याप्त समाधान कर दिया गया है जिनमें रूपान्तरण की प्रकृति तथा लागत एवं कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले नीतिगत साधनों के जरिए राज्य के हस्तक्षेप की मौजूदगी के कारण संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत में पर्याप्त विकृतियों की पुष्टि होती है।

46. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से विकृतियों को आगे लाये जाने के कारण कंपनी की लागत और कीमत में भारी विकृति आयी है और इसलिए वह इस कंपनी के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार करने के लिए पात्र नहीं है। तदनुसार प्राधिकारी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार इस निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण की कार्रवाई करते हैं।

## क) सामान्य मूल्य

47. नियमों के अनुबध्द । के पैरा 7 में यह उपबन्ध है कि:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित पद्धति से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा तथा चयन के समय उपलब्ध विश्वसनीय सूचना पर विचार किया जाएगा । किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मुद्दे के संबंध की गई जांच पर भी, जहाँ उपयुक्त हो निर्धारित समयसीमा के भीतर विचार किया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को भी किसी अनुचित विलम्ब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विषय में सूचना दी जाएगी और अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी ।

48. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों को यह सूचना दी गई थी कि घरेलू उद्योग ने यह सुझाव दिया था कि चीन में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ को बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाना चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्व में संबद्ध वस्तु के केवल चार प्रमुख उत्पादक हैं जिनमें से दो यूरोप में हैं और शेष दो भारत और चीन में हैं । अतः उत्पाद की प्रकृति और चीन एवं यूरोपीय बाजारों में उत्पाद की बिक्री पर विचार करते हुए यूरोपीय संघ, चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक उपयुक्त तीसरा देश बनता है । चीन के निर्यातकों ने अपने अभ्यावेदनों में माननीय प्राधिकारी के यूरोपीय संघ को तुलनात्मक अर्थव्यवस्था मानने के प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है । तथापि, अभ्यावेदनों में यह उल्लेख किया गया है कि यह पहले से माना जाता है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ई यू को तुलनात्मक क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं और इस प्रकार प्राधिकारी के प्रस्ताव से सहमत हैं । इसलिए प्राधिकारी यूरोपीय संघ में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत के आधार पर उपर्युक्त संदर्भित पैरा 7 के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करते हैं ।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय बाजार में विटामिन ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/ग्राम की बिक्री कीमत ऐसे निर्धारण के लिए उपलब्ध है । विटामिन-ए पामिटेट 1.7 बी एच ए/बी एच टी की औसत बिक्री कीमत जांच अवधि के दौरान यूरोपीय बाजार में कारखाना द्वार स्तर पर \*\*\*\*\* अम.डा. प्रति किग्रा. थी । चीन के निर्यात 1.7 एम आई यू/ग्राम और अल्प मात्रा में 1.6 एम आई यू/ग्राम के हैं । तथापि, विटामिन ए पामिटेट 1.6 एम आई यू/ग्राम को पूर्व में वर्णित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है । इसलिए, चीन जन गण में सामान्य मूल्य यूरोपीय बाजार में कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जो विटामिन ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/ग्राम के \*\*\*\*\* अम.डा. प्रति किग्रा. बनता है ।

**ख) निर्यात कीमतें****(i) एन एच यू सिनकेम**

50. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान विटामिन ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/ग्राम की 9900 किग्रा मात्रा का निर्यात किया है। तथापि, एन एच यू भारत को संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात नहीं करता है। इसकी मै0 एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट नामक पूर्णतः निजी अनुषंगी है जो एन एच यू के भाग के रूप में कार्य करती है जो एन एच यू द्वारा विनिर्मित इस वस्तु के निर्यात को संभालती है। तथापि, जहाँ तक भारत को निर्यात का संबंध है दूसरी मध्यवर्ती कंपनी मै0 सिनकेम है जो एन एच यू की संबंधित कंपनी है जो भारत को वास्तव में निर्यात करती है। एन एच यू वस्तु को आंतरिक बीजक के जरिए एन एच यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को बेचती है और एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स मै0 सिनकेम को दूसरा बीजक जारी करती है जो डालियन बांडेड जोन में अवस्थित एक व्यापारिक कंपनी है। सिनकेम भारत में आयातक पर वाणिज्यिक बीजक जारी करती है। निर्यात के लिए दस्तावेज वास्तव में पृष्ठ के दोनों ओर मुद्रित होते हैं और इनमें वस्तुओं के उत्पादक के रूप में एन एच यू का नाम प्रदर्शित होता है। तथापि एन एच यू, ए एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स और सिनकेम के बीजक मूल्य में काफी अंतर है।

51. चूंकि इनमें द्विस्तरीय सौदे निहित हैं और सौदे दो संबद्ध मध्यवर्ती कंपनियों के जरिए होते हैं इसलिए निर्यात कीमत को असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को सिनकेम की बिक्री के आधार पर और प्रत्येक चरण में सीधे बिक्री व्ययों और लाभ मार्जिन हेतु समायोजन करने के पश्चात परिकलित किए जाने की आवश्यकता है।

52. एन एच यू ने \*\*\*\*\* आर एम बी (8.26 आर एम बी की औसत विनिमय दर पर \*\*\*\*\* अम.डा.) मै0 एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को संबद्ध वस्तु के \*\*\* किग्रा. का हस्तांतरण किया है। एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ने संबद्ध वस्तु की इसी मात्रा को \*\*\* अम.डा. में सिनकेम को हस्तांतरण किया है। एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच सौदे एफ ओ बी निम्बो पोर्ट हैं। इसलिए, सौदों में एन एच यू संयंत्र से लदाई पत्तन तक अंतर्देशीय रिसाव और एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के वास्तविक लाभ मार्जिन और शामिल साख लागत के लिए समायोजन शामिल है।

53. सिनकेम ने एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स से विटामिन ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/ग्राम के \*\*\* किग्रा की खरीद \*\*\*\*\* अम.डा. में की और इसे \*\*\*\*\* अम.डा. के सकल बीजक मूल्य पर भारतीय बाजार में बेच दिया। सिनकेम की भारतीय उपभोक्ताओं को बिक्री सी आई एफ शर्त और डी ए/एल सी आधार पर हुई। अतः एन एच यू के कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत जानने के लिए सिनकेम के सीधे बिक्री खर्च, साख लागत और लाभ मार्जिन के लिए समायोजन किया गया था। कंपनी के अभिलेखों से सत्यापित किए गए अनुसार कमीशन, समुद्रपारीय भाड़ा और समुद्री बीमा; तथा बैंक प्रभारों को समायोजित किया गया है।

54. यह भी नोट किया जाता है कि एन एच यू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के निवल बीजक मूल्य पर निर्यातक द्वारा 17 प्रतिशत वैट चुकाया गया है और इस मूल्य के 13 प्रतिशत की दर से प्रति अदायगी प्राप्त हुई है। इसलिए निर्यातक ने वैट का 4 प्रतिशत आमेलित कर लिया है जिसे कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत जानने के लिए समायोजित करना अपेक्षित है। जहाँ तक सिनकेम के लाभ का संबंध है, सिनकेम के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध



वस्तु पर \*\*\* प्रतिशत का समग्र लाभ मार्जिन है। अतः एन एच यू के कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत जानने हेतु संबंधित निर्यातक अर्थात् सिनकेम के वास्तविक लाभ मार्जिन के लिए समायोजन करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

55. तदनुसार, एन एच यू/सिनकेम की निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत निम्नानुसार परिकलित की जाती है:-

उत्पाद	मात्रा कि.ग्रा.	निवल बीजक मूल्य सिनकेम अम. डॉ.	कुल समायोजन एनएचयूआई एंड यू	कुल समायोजन सिनकेम	वेट समायोजन	लाभ आई एंड ई ***%	लाभ सिनकेम ***%	एनएचयू फैक्टरी में निवल मूल्य	निवल निर्यात कीमत अम. डॉ.
1.7 एमआईयू	****	****	****	****	****	****	****	****	****

## (ii) अन्य

56. चीन जन. गण. के असहयोगी निर्यातकों की निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है। तदनुसार, अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत \*\*\*\* अम. डॉ. प्रति कि.ग्रा. निर्धारित की गई है।

## (ग) पाटन मार्जिन

57. कारखाना द्वार स्तरों पर निर्धारित उपर्युक्त सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमतों के आधार पर चीन के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिनों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
चीन	अम. डॉ./कि.ग्रा.	अम. डॉ./कि.ग्रा.	अम. डॉ./कि.ग्रा.	
एनएचयू/सिनकेम	****	****	****	****
अन्य सभी	****	****	****	****

## च.2. स्विट्जरलैंड

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्यातक संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर घरेलू बाजार के साथ-साथ यूरोपीय एवं भारतीय बाजारों में उसकी बिक्री करता है। तथापि, जाँच अवधि के दौरान भारत को केवल विटामिन ए पामिटेड 1.7 बीएचए/बीएचटी तथा 1.7 टोको का निर्यात किया गया है। निर्यातक ने दावा किया है कि घरेलू बाजार में उनकी बिक्री कंपनी द्वारा संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री के 2% से भी कम है और इसलिए वह सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ प्रतिनिधि बिक्री नहीं है। निर्यातक द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि ईयू अधिक उपयुक्त गृह बाजार होगा जो जाँच अवधि के दौरान बिक्री के लगभग 60% का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि करार की पाद टिप्पणी 2 में यह प्रावधान है कि

“ निर्यातक देश के घरेलू बाजार में खपत हेतु लक्षित समान उत्पाद की बिक्री को सामान्य रूप से सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पर्याप्त मात्रा माना जाना चाहिए यदि वह आयातक देश को विचाराधीन उत्पाद की

बिक्रियों के 5% या उससे अधिक हो, बशर्ते उन मामलों में इससे कम अनुपात भी स्वीकार्य होगा जहाँ साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि ऐसे कम अनुपात पर घरेलू बिक्रियाँ उचित तुलना हेतु पर्याप्त मात्रा हैं। ”

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को \*\*\*\* कि.ग्रा. 1.7 एमआईयू/जीएम के निर्यात की तुलना में उसी अवधि के दौरान घरेलू बाजार में \*\*\*\* कि.ग्रा. विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और \*\*\*\* कि.ग्रा. \*\*\*\* एमआईयू/जीएम की बिक्री की थी। अतः, समान उत्पाद की घरेलू बाजार में बिक्री भारत को बिक्रियों के 5% से अधिक है। अतः, करार के अनुसार ऐसा घरेलू बाजार की बिक्रियों की पर्याप्त मात्रा होने के कारण सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन पर विचार किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक देश के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इन बिक्रियों पर विचार किया है।

60. तथापि, निर्यातक ने यह दलील दी है कि यदि सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू बाजार में उनकी बिक्रियों पर विचार किया जाना अपेक्षित है तो बिक्री मात्राओं और व्यापार के स्तर में अंतर पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू बिक्रियाँ सीधे खुदरा ग्राहकों को कम मात्राओं में की जाती हैं और इसलिए वे निर्यात बिक्री सौदों के साथ तुलनीय नहीं हैं। दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के पत्र के माध्यम से निर्यातक से व्यापार समायोजनों के स्तरों तथा उचित तुलना हेतु उनके द्वारा किए गए दावों के अनुसार कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों को निर्धारित करने एवं उन्हें दर्शाने को कहा गया था। अपने दिनांक 24 अप्रैल और 16 मई, 2007 के पत्र के माध्यम से निर्यातक ने स्विट्जरलैंड में सीधे ग्राहकों को कम मात्राओं में बिक्रियों के कारण घरेलू बिक्रियों के संबंध में कीमत तुलनीयता और प्रत्यक्ष बिक्री व्ययों को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए समायोजनों को निर्धारित करने के लिए कुछेक सूचना एवं तर्क प्रस्तुत किए थे।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 1 के नियम 6(i) तथा करार के अनुच्छेद 2.4 में यह प्रावधान है कि “प्रत्येक मामले में अर्हता के आधार पर व्यापार की स्थितियों एवं निबंधनों में अंतर, कराधान, व्यापार का स्तर, मात्रा, भौतिक विशेषताएँ तथा अन्य अंतर जिनसे कीमत तुलनीयता का प्रभावित होना प्रदर्शित होता है, सहित कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अंतरों के लिए उचित छूट दी जाएगी।” उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्यातक के दावों की निम्नानुसार जाँच की गई है :-

(क) घरेलू बाजार में सौदे की कम मात्रा के लिए समायोजन के निर्यातक के दावे की जाँच की गई है। यह दावा किया गया है कि घरेलू बिक्रियाँ कम मात्राओं में हैं और घरेलू बाजार में प्रति सौदा बेची गई औसत मात्रा 41 कि.ग्रा. है जबकि भारतीय बाजार में प्रति बिक्री औसत मात्रा 416 कि.ग्रा. है। यह तर्क दिया गया है कि ऑर्डर की मात्रा में अंतर से संबंधित कीमतों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे कम ऑर्डर मात्राओं पर एक न्यूनतम मात्रा सरचार्ज लेते हैं। इसके समर्थन में कम मात्रा वाले कुछ निर्यात बीजक प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि, घरेलू बाजार में कम ऑर्डर सरचार्ज का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि मात्राओं का कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है और तुलना के प्रयोजनार्थ समायोजन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, निर्यातक ने भारत में बिक्री सौदों हेतु 300 कि.ग्रा. से कम और 300 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा की प्रति इकाई कीमत में अंतर के आधार पर समायोजन का निर्धारण किया है। तथापि, ये मात्रा अंतर और कम मात्रा सरचार्ज निर्यात बिक्री के संदर्भ में हैं और गृह बाजार में मात्राओं के कारण कीमतों में ऐसे किसी अंतर का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि ऐसे समायोजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) मात्राओं के संबंध में समायोजनों के अन्तर्गत निर्यातक ने इन आधारों पर व्यापार समायोजन के स्तर का दावा किया है कि घरेलू बिक्रियाँ अधिकांशतः प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को की गई हैं जबकि भारत को निर्यात बिक्रियाँ अधिकांशतः पुनः बिक्रीकर्ताओं को की गई हैं, इससे भी कीमत तुलनीयता पर प्रभाव पड़ता है। यह भी तर्क किया गया है कि स्विटजरलैंड या यूरोपीय बाजारों में प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की कीमतें पुनः बिक्रीकर्ताओं के कीमतों की तुलना में आमतौर पर 5 से 7% अधिक होती है। इस दावे के समर्थन में उन्होंने प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं और स्विस् बाजार में पुनर्बिक्रीकर्ताओं को उसी उत्पाद के समकालिक बीजकों के साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है जिनसे यह संकेत मिलता है कि इन कीमतों के बीच लगभग 5% का अंतर है। यह तर्क दिया गया है कि पुनः बिक्रीकर्ताओं को इस चिह्नांकन की अनुमति दी गई है ताकि वह अपने खर्चों और लाभ पर ध्यान रख सकें। आमतौर पर पुनः बिक्रीकर्ता या एजेंट को एक कमीशन; या अपनी कीमतों में एक चिह्नांकन प्राप्त होता है जो व्यापार में सामान्यतः उसके खर्चों और मार्जिनों तथा 3 से 5% तक कमीशन/मार्जिन की पूर्ति हेतु होता है। अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि इसके लिए 3% का समायोजन न्यायोचित है।

(ग) निर्यातक ने घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष बिक्री खर्चों अर्थात् संयंत्र से भाण्डागारों तक अंतर्देशीय भाड़ा और संबंधित बीमा, भण्डारण एवं प्रहस्तन व्यय, भाण्डागार से उपभोक्ता तक ले जाने का भाड़ा और संबंधित बीमा खर्च के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। जहाँ तक भाण्डागारों से घरेलू उपभोक्ताओं तक के घरेलू मालभाड़े का संबंध है, निर्यातक ने डीएचएल कुरियर के जरिए की गई सुपुर्दगी में आई वास्तविक लागत के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और तदनुसार संशोधित मालभाड़ा लागत की गणना \*\*\* अम. डालर प्रति कि.ग्रा. के रूप में की गई है।

62. तदनुसार, स्विटजरलैंड में विचाराधीन उत्पाद के लिए कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निम्नानुसार ज्ञात किया गया है :

घरेलू बाजार में प्रतिनिधि कीमत	मात्रा कि.ग्रा. में	यूरो कीमत	में	अम. डॉ. में कीमत	विनिमय दर	समायोजन अम. डॉ./ कि.ग्रा.	सामान्य मूल्य अम. डॉ./कि.ग्रा.
विटा. ए पाम 1.7 बीएचए/ बीएचटी	****	****		****	****	****	****
विटा. ए पाम 1.7 टीओसीओ	****	****		****	****	****	****

(ख) निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन

(i) डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स

63. डीएनपी जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के \*\*\* कि.ग्रा. की निर्यात बिक्रियों की जानकारी दी है जिसमें विटामिन ए पाल्मिटेट 1.7बीएचए/बीएचटी और 1.7 टीओसीओ शामिल हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को बिक्री हेतु डीएनपी के उत्पाद सामान्यतः भारत को भेजे जाने से पहले नीदरलैंड से सिंगापुर को भेजे (जलपोत द्वारा) जाते हैं। निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इन संबंधित उत्पादों का प्रहस्तन डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के सिंगापुर में एशिया पैसिफिक हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह एक भाण्डागार के साथ एक व्यापारिक संगठन है और उत्पादों का भारत को और अन्य एशिया पैसिफिक देशों को पुनः निर्यात करता है। निर्यातक ने अनुरोध किया है कि प्रश्नावली के उत्तर में बताई गई कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अंतिम निर्यात कीमत है और संबंधित कम्पनियों अर्थात् डीएनपी स्विटजरलैंड और डीएनपी सिंगापुर के बीच कीमत तंत्र इस जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

64. निर्यातक ने सिस्सेन स्थल से वेनलो, नीदरलैंड (भाण्डागार) तक के अंतर्देशीय मालभाड़े और संबंधित बीमा खर्चों, भण्डारण एवं प्रहस्तन प्रभारों स्विटजरलैंड से सिंगापुर और सिंगापुर से भारत तक के विदेशी भाड़ों और संबंधित बीमा खर्चों, और पोत परिवहन प्रभारों पर हुए प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में सूचना प्रदान की है। पैकिंग खर्चों के संबंध में किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें लागत में शामिल किया गया है और निर्यात पैकिंग और घरेलू पैकिंग के बीच कोई अंतर नहीं है। तदनुसार, कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार बनती है।

भारत निर्यात कीमत	को	मात्रा कि.ग्रा. में	कीमत यूरो	दर यूरो/कि.ग्रा.	मूल्य अम. डॉ.	दर अम.डॉ./ कि.ग्रा.	समायोजन अम. डॉ./ कि.ग्रा.	निवल कीमत अम. डॉ./कि.ग्रा.
विटा. ए पाम 1.7 बीएचए/ बीएचटी	ए	****	****	****	****	****		****
विटा. ए पाम 1.7 टीओसीओ	ए	****	****	****	****	****		****

65. स्विटजरलैंड के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और डीएनपी के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत के आधार पर इस सहयोगी निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का आकलन निम्नानुसार किया गया है :

		सामान्य मूल्य अम. डॉ./ कि.ग्रा.	मात्रा कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अम. डॉ./कि.ग्रा.	मात्रा कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अम. डॉ./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन मूल्य
विटा. ए पाम 1.7 बीएचए/ बीएचटी	ए	****	****	****	****	****	****
विटा. ए पाम 1.7	ए	****	****	****	****	****	****

टीओसीओ						
भारित औसत	****	****	****	****	****	****
					21%	

66. डीएसएम ने अपने प्रकटन के बाद के अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि चूँकि भारतीय कानून में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त मात्राओं में माने जाने के लिए घरेलू बिक्रियों हेतु निर्धारित सीमा की व्यवस्था नहीं है इसलिए प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में केवल डब्ल्यूटीओ करार पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्विट्जरलैंड में की गई घरेलू बिक्रियाँ उसके कुल बिक्रियों की तुलना में काफी कम (2%) से कम थीं, अपनी खुद की बुद्धिमता के आधार पर इसका मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि किसी बाजार विशेष की स्थिति अर्थात् स्विट्जरलैंड में बिक्रियाँ काफी कम मात्राओं में की गई हैं जबकि भारत को निर्यात के लिए की गई बिक्रियाँ स्विट्जरलैंड में मौजूद काफी अधिक मात्राओं में की गई हैं जिस पर स्विट्जरलैंड में सामान्य मूल्य के निर्धारण में विचार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ उपयुक्त बाजार है और न कि स्विट्जरलैंड। निर्यातक ने यह भी टिप्पणी की है कि भारत औसत पाटन मार्जिन की गणना भारत औसत सामान्य मूल्य और भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर की जानी चाहिए।

67. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन के बाद के अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि मौके पर सत्यापन किए बिना डीएसएम द्वारा दिए गए आंकड़ों और अन्य दावों को स्वीकार करना अनावश्यक और तथ्यरहित नहीं है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी तर्क दिया है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में डीएसएम समेत स्विट्जरलैंड के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात् तीसरे देश (यूरोपीय संघ) की सूचना या भारत में दी गई या देय कीमत जो नियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित ढंग से विधिवत रूप से समायोजित हो, पर आधारित होना चाहिए।

68. इस सम्बन्ध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्विट्स बाजार में की गई बिक्रियाँ भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्राओं में की गई पाई गई हैं (जो भारत को बिक्रियों का 20% से अधिक हिस्सा हैं) और इसलिए इन्हें भारत को निर्यातों के साथ तुलना के लिए उपयुक्त समझा गया है तथापि, निर्यातक ने कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले कतिपय कारकों के संबंध में अपने घरेलू बाजार की कीमतों में कुछेक समायोजनों का दावा किया है और ऐसे समायोजन जो निर्यातक द्वारा प्रदर्शित एवं साक्ष्यों के साथ उचित ठहराए जा सकते हैं, को प्राधिकारी ने स्वीकार किया है। न्यूनतम मात्रा संबंधी के लिए किए गए समायोजनों का दावा घरेलू बिक्रियों के संदर्भ में निर्यातक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सका है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में निर्यातक के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं। जहाँ तक गणना किए गए पाटन मार्जिन में हुई गलती का संबंध है, पाटन मार्जिन का निर्धारण मध्यवर्ती पाटन मार्जिनों के भारत औसत, सबटाइप स्तरों (उत्पाद सबटाइप्स की निर्यात मात्राओं पर भारत) पर निर्धारित के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त निर्यातक के लिए उक्त आधार पर पाटन मार्जिन की गणना उचित है अतः पाटन मार्जिन में किसी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

69. जहाँ तक घरेलू उद्योग के तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक ने अपने पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की थी और उसके सत्यापन की पेशकश की थी। मामले के वास्तविक मैट्रिक्स के आधार पर प्राधिकारी ने सत्यापन के बिना आंकड़ों को जिस सीमा तक ये तथ्यपूर्ण हैं, स्वीकार करने का निर्णय लिया है और तदनुसार, जैसाकि पहले बताया गया है कंपनी की घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना की गई है। अतः प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस तर्क में कोई ठोस आधार नहीं दिखाई देता है कि स्विस निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण ईयू बाजार में बिक्री कीमत के आधार पर या लागत जमा लाभ के परिकलित आधार पर किया जाना चाहिए।

## (ii) अन्य निर्यातक

70. अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातकों के आंकड़ों के अनुसार समायोजन करने के पश्चात सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में स्विट्जरलैंड से सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत की तुलना स्विट्जरलैंड के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, स्विट्जरलैंड के सभी अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है :

सामान्य अम.डा./कि.ग्रा.	मूल्य	न्यूनतम निर्यात कीमत यूरो/कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अम. डा./कि.ग्रा.	समायोजन अम. डा./कि.ग्रा.	निवल निर्यात कीमत अम.डा./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अम. डा./ कि.ग्रा.
84.420		****	****	****	****	****
						33%

## च.4. पाटन मार्जिन : सारांश

उत्पाद		देश	निर्यातक	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
				अम.डा./कि.ग्रा.	
विटामिन- पामिटेट	ए	स्विट्जरलैंड	मै. डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स		
		स्विट्जरलैंड	सभी अन्य		
		चीन	सिनकेम के साथ एनएचयू		
			सभी अन्य		

इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक हैं और निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

## छ. क्षति निर्धारण

### छ.1. निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

#### छ.1.1. डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लि. (डीएनपी)

71. जांच शुरूआत के पश्चात अपने निवेदन में डीएनपी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि चीन से आयातित वस्तु और घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तें स्विस् निर्यातों तथा घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा से सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं, अतः इस समामले में क्षति का संचयी आकलन न्यायोचित नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि जहाँ स्विस् उत्पाद भारतीय बाजार में अनेक वर्षों से मौजूद हैं वहीं चीन के उत्पादों का भारतीय बाजार में प्रवेश वर्ष 2003 से हुआ है और तब से इसमें तीन गुना वृद्धि हो गई है। जहाँ मात्रा की दृष्टि से चीन के निर्यातों में भारी वृद्धि हुई है, वहीं स्विट्जरलैण्ड से निर्यात तकरीबन स्थिर रहे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में स्विस् उत्पाद के बाजार हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है। स्विस् कीमतों की तुलना में चीन के उत्पादों की कीमतें भी काफी कम हैं, जो यह दर्शाता है कि इन उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ सर्वथा भिन्न हैं, अतः क्षति का संचयी आकलन जरूरी नहीं है।

72. डीएनपी ने आगे यह तर्क दिया है कि जिस अवधि के लिए ईयू तथा अन्य देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू था, उससे संबंधित आंकड़ों को जांच के दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि शुल्क लगा देने से आयातों में अचानक कमी आ गई थी और घरेलू उद्योग का एकाधिकार लगभग स्थापित हो गया था। अतः यह अस्थायी स्थिति घरेलू उद्योग की बिक्री में स्वाभाविक अथवा सम्भावित गिरावट नहीं दर्शाती। डीएनपी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग निर्यात में हुए घाटे की घरेलू बाजार में भरपाई के लिए असाधारण कीमत अर्जित करने की आशा रखता है, अतः घरेलू उद्योग के निर्यात तथा घरेलू बिक्री का विश्लेषण अलग-अलग नहीं किया जाना चाहिए। डीएनपी ने आगे यह भी तर्क दिया है कि भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के अधिकतम बिक्री मूल्य का निर्धारण भारत के औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश द्वारा होने के कारण इसके निर्यात कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत कटौती अथवा कम कीमत पर बिक्री संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की बिक्री फार्मूलेशन विनिर्माताओं और पुनः बिक्री करने वालों को करता है। पुनः बिक्री करने वालों हेतु कीमतें डीपीसीओ कीमतों से कम होती हैं, जिनमें पुनः बिक्री करने वालों के व्यय तथा लाभ की मांजिन का प्रावधान होता है। अतः डीएनपी का पहुंच मूल्य डीपीसीओ कीमत के निकट होने के कारण कीमत कटौती/कम कीमत पर बिक्री संबंधी कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

73. यह भी तर्क दिया गया है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर मूल सीमाशुल्क घटाकर आधे से भी कम (अर्थात् 35% से घटाकर 15%) कर दिया गया है, जिसने स्पष्टतः आयातित सामग्री को उत्तरोत्तर अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है, बावजूद इस तथ्य के, कि इस अवधि में डीएनपी ने अपनी सीआईएफ कीमत नहीं घटाई है, जो इस बात का संकेत है कि इससे पाटन अथवा वास्तविक क्षति नहीं हुई है। वर्ष 2001 से 2005 तक अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य भी 48 रुपये से बढ़कर 44 से कुछ कम हो गया है। ये दोनों परिवर्तन सरकार की नीति के परिणामस्वरूप हुए हैं और आयातित सामग्री की पसन्द को स्पष्ट करने में सहायक हैं। अतः स्विस् निर्यातों और घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

74. प्रकटीकरण के पश्चात अपने निवेदन में डीएसएम ने क्षति तथा कारणात्मक संबंधों के तर्कों को दोहराया है। पहले प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में उन्होंने अपने एक रीसेलर/आयातक की बिक्री से संबंधित सूचना भी उन आयातक के माध्यम से प्रस्तुत की है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीएसएम के आयातक/रीसेलर ने उचित समय पर प्रश्नावली के उत्तर अथवा अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। अतः

जांच के इस चरण में रीसेलर द्वारा अपनी बिक्री कीमत के बारे में दी गई सूचना रिकार्ड में दर्ज नहीं की जा सकती। जहाँ तक डीपीसीओ कीमत तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर इसके प्रभाव का प्रश्न है, इसका पर्याप्त विवेचन इस जांच परिणाम में कारणात्मक संबंध के विश्लेषण में किया गया है।

### छ.1.2 एनएचयू/सिनकेम के विचार

75. एनएचयू/सिनकेम ने प्रारम्भिक जांच परिणाम के पश्चात अपने निवेदन में तर्क प्रस्तुत किया है कि भारत में आयात के उदारीकरण, घटते टैरिफों, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के कारण और भारत, जो विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, में घरेलू माँग बढ़ जाने से आयातों की मात्रा बढ़ गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों की निर्यात से निराशाजनक आय, जिसका उल्लेख याचिका में भी किया गया है, के कारण जांच अवधि के दौरान आय अथवा लाभ में कमी आई है। आगे यह तर्क भी दिया गया है कि घरेलू उद्योग को लगाई गई पूंजी पर 26% की अनुचित दर से आय होती है और आवेदक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है और 2004-06 के बीच अधिग्रहणों की प्रक्रिया में इसे पूंजी जुटाने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी, जैसा कि इसकी पब्लिक डोमेन वेबसाइट में दर्शाया गया है। चीन के निर्यातकों ने यह भी तर्क दिया है कि भारत में वस्तुओं से संबंधित सार्वजनिक नीति की प्रमुख चिंता यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य में विटामिन ए के महत्व के मदेनजर सम्बद्ध वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हों तथा सस्ती हों, न कि भेषज उद्योग को लाभ पहुंचाना। प्रकटीकरण के पश्चात की गई टिप्पणियों में निर्यातक ने क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में अपने तर्कों को दोहराया है।

### द.1.3 डीपीसीओ मुद्दा

76. चीन जन. गण. और स्विट्जरलैण्ड के निर्यातकों ने अपने निवेदनों में कहा है कि भारत सरकार का औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 आयातित फार्मूलेशनों पर लागू होता है, अतः सुनवाई के चरण में घरेलू उद्योग का यह निवेदन गुमराह करने वाला है कि कीमत परिसीमन आयातक द्वारा भारत में पुनः बिक्री कीमत पर ही लागू होता है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि डीपीसीओ द्वारा निर्धारित कीमत परिसीमन भारत में सम्बद्ध वस्तुओं की सभी बिक्रियों पर लागू होता है और अंतिम प्रयोक्ता हेतु अंतिम बिक्री कीमत निर्धारित करता है। चूंकि आयात अधिकांशतः व्यापारियों/रीसेलरों द्वारा किए गए हैं, जो इन वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय ग्राहकों/प्रयोक्ताओं को करते हैं, अतः उनकी पुनः बिक्री मार्जिन का ध्यान रखने के लिए आयातक/व्यापारी द्वारा उत्पाद की खरीद पहुंच मूल्य पर ही की जानी चाहिए, जो डीपीसीओ के कीमत परिसीमन से कम है। इसी एकमात्र कारण के आधार पर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण डीपीसीओ कीमत परिसीमन पर करने से, जैसा कि आवेदकों ने अनुरोध किया है, भारतीय बाजार से निर्यातक बाहर हो जाएंगे और बाजार पहुंच से गैर कानूनी तरीके से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आयातकों के लिए लाभ और बिक्री के अंतिम स्थान से पूर्व भारत में परिवहन/सम्भार तंत्र लागत, जैसी भी स्थिति हो, और भारत में अंतिम पुनः बिक्री कीमत निश्चित रूप से डीपीसीओ परिसीमन कीमत से अधिक होगी और इस प्रकार भारत में बिक्री के लिए पात्र नहीं होगी। अतः संबंधित निर्यातकों द्वारा ऐसी बाजार पहुंच तभी सम्भव है, जब अधिक से अधिक क्षति रहित कीमत (यदि कम नहीं भी हो) डीपीसीओ कीमत परिसीमन से कम हो और आयातकों (ग्राहकों को अंतिम बिक्री के स्थान से पूर्व आयातक द्वारा प्रयुक्त अन्य कोई वितरण चैनल) के लिए लाभ तथा भारत के भीतर परिवहन/सम्भार तंत्र लागत की पर्याप्त गुंजाइश बचती हो।



## छ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के दावों से संबंधित हितबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त विचारों को नोट करते हैं और उठाए गए मुद्दों तथा क्षति के संबंध में किए गए दावे की जांच करते हैं, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

### छ.2.1 क्षति का संचयी आकलन

78. पाठनरोधी नियमावली के अनुबंध II(iii) में यह अपेक्षा की गई है कि जब एकाधिक देशों के उत्पाद के आयातों की पाठनरोधी जांच एक साथ की जा रही हो, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे निर्यातों के प्रभाव का संचयी आकलन किया जाएगा, यदि यह निर्धारित होता हो कि :-

- (i) यदि अलग-अलग देशों के आयात न्यूनतम से अधिक हों अथवा उनका संचयी योगदान आयातों के 7% से अधिक हो;
- (ii) अलग-अलग देशों के विरुद्ध पाठन मार्जिन 2% से अधिक हो; और
- (iii) आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के संदर्भ में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित हो।

79. डीएनपी ने तर्क दिया है कि उनके द्वारा निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं की कीमत चीन जन. गण. से जिस कीमत पर आयात किया जा रहा है उससे काफी भिन्न हैं अतः इन दोनों उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव है, इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन में संचित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं के पाठित आयातों का भारतीय बाजार में प्रवेश एक साथ हो रहा था। यद्यपि 2003 तक चीन से सम्बद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं हुआ था दोनों देशों ने जांच अवधि के दौरान तुलनात्मक मात्राओं का निर्यात किया और प्रत्येक सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के पाठन की मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक थी। घरेलू उत्पाद तथा सम्बद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा आपूर्तित उत्पाद समान वस्तुएं हैं और उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। विभिन्न देशों से आयातों की सौदेवार सूचना यह दर्शाती है कि आयात भेषज उद्योग के वास्तविक प्रयोक्ताओं और व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है, जो इस सामग्री का आयात भेषज तथा अन्य प्रयोक्ता उद्योगों को पुनः बिक्री के लिए कर रहे हैं। संबंधित देशों द्वारा आपूर्तित वस्तुओं का भारतीय बाजारों में प्रवेश वितरण के समान चैनलों, उसी अवधि के दौरान तुलनात्मक बिक्री चैनलों और समान वाणिज्यिक स्थितियों में हो रहा है। घरेलू उत्पादक तथा सम्बद्ध देशों के निर्यातक उत्पाद की बिक्री ग्राहकों के एक ही वर्ग को कर रहे हैं। सम्बद्ध देशों के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की उल्लेखनीय कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री हो रही है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद एवं चीन के निर्यातकों व स्विस निर्यातकों द्वारा निर्यातित उत्पाद एक ही बाजार में आपस में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का अभिमत है कि इस मामले में क्षति की संचयी आकलन करना उचित है।

### 8.3. क्षति की जांच एवं कारणात्मक संबंध

80. अनुबंध- ॥ के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली क नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच की जाएगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत करते हैं “ ..... सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..... ” । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना जरूरी समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक मंदी लाना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना था, जो अन्यथा उल्लेखनीय सीमा तक होता ।

81. चूंकि विभिन्न शक्तियों के विटामिन ए पामीटेड का अंतिम उपयोग समान होता है अतः वर्तमान जांच में सम्बद्ध वस्तुओं को उसकी सभी शक्तियों और रूपों में कवर किया जाएगा । तदनुसार उद्योग की समग्र स्थिति तथा घरेलू उद्योग के विटामिन ए व्यापार पर आयातों के प्रभाव की सुसंगत सीमा तक जांच की गई है ।

82. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच हेतु नियमावली के अनुबंध ॥ के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, बिक्री से निवल आय, पाटन की सीमा तथा मार्जिन आदि पर विचार किया गया है । घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक मानदण्डों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा आदि की जांच इस खण्ड में की गई है ।

#### द.3.1 पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव : आयात की मात्रा तथा बाजार हिस्सा

##### (क) आयात की मात्रा

83. जहाँ तक पाटित आयातों की मात्रा का प्रश्न है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या निरपेक्ष रूप में अथवा उत्पादन की तुलना में अथवा भारत में खपत की तुलना में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

84. आवेदक ने आईबीआईएस द्वारा स्रोत से संकलित आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि क्षति की जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों सहित अनेक स्रोतों से आयात किया गया है । डीजीसीआईएस से भी सौदेवार आयात आंकड़े जांच के प्रयोजनार्थ प्राप्त किए गए हैं । तथापि, डीजीसीआईएस के आंकड़ों एवं सहयोगी निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों की जांच से यह संकेत मिलता है कि डीजीसीआईएस ने जांच अवधि से संबंधित आयात आंकड़ों को व्यापक रूप से कम बताया है । डीजीसीआईएस द्वारा सूचित आयातों की तुलना में सहयोगी निर्यातकों ने काफी अधिक मात्राओं के निर्यातों की सूचना दी है । अतः आयात की मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ

आयातों की गणना डीजीसीआईएस के आयात आंकड़ों के सहयोगी निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों में समायोजन के बाद की गई है। तदनुसार सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निम्नानुसार है :-

मात्रा कि. ग्रा. में

देश	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
स्विट्जरलैण्ड	2197	2370	1200	1560	11240.7	7494
प्रवृत्ति	100	108	55	71	511	341
चीन	0	0	2005	1750	9900	6600
प्रवृत्ति	0	0	100	87	493	329
कुल सम्बद्ध देश	2197	2370	3205	3310	21140.7	14094
प्रवृत्ति	100	108	146	151	962	642
अन्य	8096	1549	458	25	1315	877
प्रवृत्ति	100	19	6	0	16	11
कुल	10293	3919	3663	3335	22456	14970
प्रवृत्ति	100	38	36	32	218	145

85. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति की जांच की अवधि में, विशेष रूप से जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में जारी वृद्धि हुई है। स्विट्जरलैण्ड से आयातों में 2003-04 तक गिरावट के बाद वृद्धि हुई है। चीन से आयात 2003-04 तक गिरावट के बाद वृद्धि हुई है। चीन से आयात 2003-04 में शुरू हुए और तत्पश्चात इनमें अत्यधिक वृद्धि हुई। सम्बद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि कुल आयातों में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

#### (ख) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग पर वास्तविक तथा सम्भावित प्रभाव

86. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच इसकी क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग एवं इन मानदण्डों पर पाटित आयातों के प्रभाव, यदि कोई हो, के आधार पर की गई है।

87. घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि उनके तरल संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता, जहां सम्बद्ध वस्तुओं का विनिर्माण होता है, सिंगल शिफ्ट के आधार पर 110 मी. टन प्रति वर्ष है। तथापि, संयंत्र का प्रचालन तीन पारियों में किया जाता है, तदनुसार उपलब्ध क्षमता 330 मी. टन प्रति वर्ष है। इस क्षमता की तुलना में संयंत्र का उपयोग लगभग 67% किया जाता है। यह नोट किया जाता है कि यह स्थापित क्षमता केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए ही नहीं है और इस संयंत्र में कम्पनी द्वारा लगभग 35 विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है। अलग-अलग उत्पाद का उत्पादन मांग के अनुसार वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार उत्पादक की क्षमता का आकलन तीन शिफ्टों में प्रचालन, जिसके लिए संयंत्र वास्तविक रूप से उपलब्ध है और विचाराधीन उत्पाद सहित संयंत्र के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के आधार पर किया गया है। तदनुसार, क्षमता तथा क्षमता उपयोग की गणना निम्नानुसार की गई है :-

वर्ष	स्थापित क्षमता (कि.ग्रा.)	उत्पादन (सभी उत्पाद) कि.ग्रा.	सूचीबद्ध क्षमता उपयोग (%)
2000-01	100	100	47%
2001-02	100	72	33%
2002-03	100	104	48%
2003-04	100	119	55%
2004-05	100	122	57%
जांच अवधि वार्षिकीकृत	100	144	67%

88. उपर्युक्त जांच दर्शाती है कि जांच अवधि के दौरान तरल संयंत्र का वार्षिकीकृत उत्पादन तथा क्षमता उपयोग जांच अवधि सहित पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है। अतः तरल संयंत्र के कुल उत्पादन को देखते हुए क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट दर्शाता प्रतीत नहीं होता।

89. बहरहाल, घरेलू उद्योग द्वारा विटामिन ए पामिटेड के उत्पादन की जांच निम्नानुसार की गई है :-

विटामिन ए का उत्पादन	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	मात्रा कि.ग्रा. में जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू बाजार हेतु उत्पादन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	135	158	96	126
निर्यात हेतु उत्पादन	****	****	****	****	****
कुल उत्पादन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	135	173	182	212

90. उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जहाँ घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं का कुल उत्पादन निरंतर वृद्धि दर्शाता है, वहीं घरेलू बाजार हेतु उत्पादन में वर्ष 2003-04 तक स्वस्थ वृद्धि होने के बाद भारी गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात में भारी वृद्धि हुई है।

(ख) बिक्री पर वास्तविक तथा सम्भावित प्रभाव एवं घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा :

91. घरेलू बिक्री की मात्रा तथा घरेलू बिक्री पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच घरेलू उद्योग की कुल बिक्री, मांग तथा बाजार हिस्से के आधार पर की गई है :-

बिक्री	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	मात्रा कि. ग्रा. में जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू बिक्री	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	234	233	106	166
आबद्ध खपत	****	****	****	****	****

प्रवृत्ति	100	57	118	90	100
आबद्ध खपत सहित डीआई बिक्री	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	128	164	97	127

92. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू बिक्री तथा घरेलू उद्योग की कुल बिक्री में वर्ष 2003-04 तक उल्लेखनीय वृद्धि होने के बाद भारी गिरावट आई है। निर्यातकों ने तर्क दिया है कि वर्ष 2003-04 तक उत्पादन और बिक्री में सुधार ईयू, जॉर्जिया तथा सिंगापुर के विरुद्ध लागू शुल्क के कारण हुआ और तत्पश्चात् इन देशों से पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने के बाद अनेक स्रोतों से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट अवश्यभावी थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतिपय देशों सेस पाटित आयातों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए पहले पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, क्योंकि घरेलू उद्योग के उबरने के रूप में इसका वांछित प्रभाव हुआ था। तथापि, 2004-05 से उत्पादन तथा बिक्री में गिरावट चीन तथा स्विट्जरलैण्ड से पाटित आयातों में वृद्धि के साथ हुई जैसा कि पिछले खण्ड में दर्शाया गया है, जबकि जिन देशों के विरुद्ध पहले शुल्क लगाया गया था, उनसे आयात शुल्क हटा लिए जाने के बाद भी नहीं बढ़ा है। अतः निर्यातकों के तर्क वैध नहीं हैं।

93. उत्पाद की घरेलू बिक्री और आयात की पूर्वोक्त संशोधित मात्राओं को ध्यान में रखकर सम्बद्ध वस्तुओं की मांग तथा बाजार हिस्से की जांच की गई है।

मात्रा कि. ग्रा. में

विटामिन ए की माँग	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि वार्षिकीकृत
आबद्ध खपत सहित घरेलू बिक्री	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	128	164	97	127
कुल आयात	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	38	36	32	145
कुल घरेलू माँग	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	96	119	74	133

94. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जहाँ सम्बद्ध वस्तुओं की माँग में लगभग 33% की लगातार वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री में 2003-04 तक उल्लेखनीय वृद्धि होने के बाद अत्यधिक गिरावट आई। सम्बद्ध देशों से आयातों में 500% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि कुल आयातों में केवल 145% की वृद्धि हुई। सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों का भारत के कुल आयातों में हिस्सा 94% है।

95. घरेलू उद्योग और पाटित आयातों के बाजार हिस्से की जांच भी की गई है, जो निम्नानुसार है :-

बाजार हिस्सा	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग	100	133	138	131	95
स्विट्जरलैण्ड	100	112	46	96	256
चीन	0	0	100	87	494
अन्य देश	100	20	5	0	8

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क 2003-04 तक लागू था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से पाटित आयातों की उल्लेखनीय मात्रा में भारतीय बाजारों में प्रवेश की शुरुआत 2004-05 से हुई। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बीच की अवधि में सुधार होने के बाद गिरावट आई।

97. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप में तथा भारत में आयात भारत में उत्पादन तथा भारत में खपत के सापेक्ष वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया कि आयात की मात्रा में वृद्धि माँग में वृद्धि की तुलना में अधिक है। अन्य शब्दों में आयातों में वृद्धि की दर माँग में वृद्धि की दर से अधिक थी।

### छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

98. जहाँ तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का प्रश्न है, प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमतों में उल्लेखनीय सीमा तक मंदी लाना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय सीमा तक हो।

#### (क) कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

99. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करें तथा शुल्कों, रिबेटों, छूट तथा कमीशन को छोड़कर बिक्री कीमत तथा मालभाड़े एवं परिवहन के आधार पर किया गया है। आयातों के पहुँच मूल्य का निर्धारण 1% पहुँच प्रभार तथा लागू मूल सीमाशुल्क सहित भारत औसत सीआईएफ आयात कीमत के आधार पर किया गया है। यह जांच करने के लिए कि क्या पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर उल्लेखनीय कीमत कटौती प्रभाव हुआ है, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री, प्राप्ति की तुलना पाटित आयातों के पहुँच मूल्य से की गई।

100. कम कीमत पर बिक्री के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत एवं एसजीए व्ययों तथा लाभ की समुचित मार्जिन को ध्यान में रखकर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है। पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव के निर्धारण हेतु पाटित आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना सम्बद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत से की गई।

		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि वार्षिकीकृत	
निर्माण एवं बिक्री की लागत		*****	*****	*****	*****	*****	
प्रवृत्ति		100	83	78	101	89	
निवल बिक्री प्राप्ति		*****	*****	*****	*****	*****	
प्रवृत्ति		100	104	92	85	85	
पहुँच मूल्य							

स्विट्जरलैण्ड	4014.15	3982.98	3889.60	3842.42	3812.81	
चीन	0.00	0.00	3402.25	3284.27	3535.91	
सम्बद्ध देश	4014.15	3982.98	3584.72	3547.32	3561.07	
कीमत कटौती						
स्विट्जरलैण्ड	*****	*****	*****	*****	*****	5-15%
चीन	*****	*****	*****	*****	*****	10-20%
सम्बद्ध देश	*****	*****	*****	*****	*****	10-20%
क्षतिरहित कीमत					*****	
कम कीमत पर बिक्री					*****	
स्विट्जरलैण्ड					*****	10-20%
चीन					*****	15-25%
सम्बद्ध देश					*****	15-25%

101. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि सम्बद्ध देशों के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति तथा क्षति रहित कीमत से बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई हैं।

### (ख) कीमत दबाव तथा मंदी

102. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत दबाव के प्रभाव की जांच हेतु घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की तुलना उत्पादन लागत से की गई। आंकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि क्षति की जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत में गिरावट आई है, तथापि बिक्री से आय में गिरावट उत्पादन लागत में आई गिरावट से काफी अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उत्पाद कीमत नियंत्रण के अध्यक्षीन है, अतः घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने के लिए कीमतें बढ़ाने से रोक दिया गया। तथापि यह भी प्रतीत होता है कि पाटित आयातों के कीमत प्रभाव ने घरेलू उद्योग पर दबाव बनाकर अपने बाजार हिस्से को कायम रखने के उद्देश्य से अपनी कीमतें कम रखने के उद्देश्य से अपनी कीमतें कम रखने पर विवश कर दिया है।

103. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि निरपेक्ष रूप में तथा बाजार हिस्से के रूप में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि से और घरेलू बाजार में कीमतों में मंदी लाकर और बाजार हिस्से को नुकसान पहुंचाकर पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की मात्रा तथा कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

### छ.3.3 क्षति के अन्य कारकों की जांच

104. क्षति से संबंधित कुछेक कारकों अर्थात् क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री तथा बाजार हिस्से में वास्तविक तथा सम्भावित गिरावट की जांच पिछले खण्ड में की गई थी और यह पाया गया कि :-

(क) घरेलू बाजार में सम्बद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के बावजूद क्षति की अवधि में घरेलू बाजार हेतु घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं बिक्री में 2003-04 तक उल्लेखनीय वृद्धि के बाद कमी आ गई है। घरेलू बाजार में अच्छी मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग को उत्पादन बढ़ाने से रोक दिया गया।

(ख) यद्यपि घरेलू उद्योग के पास सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन व घरेलू बाजार में बिक्री की क्षमता है, तथापि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाया है।

(ग) वर्ष 2003-04 तक स्वस्थ वृद्धि के बाद घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी कमी आई, जिसकी परिणति घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के रूप में हुई। घरेलू उद्योग, मांग में वृद्धि होने से लाभान्वित नहीं हुआ है।

(क) लाभ पर वास्तविक तथा सम्भावित प्रभाव

105. घरेलू बाजार में सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	निर्माण व बिक्री की लागत प्रति मी. टन (रु. में)	बिक्री कीमत/मी. टन (रु.)	लाभ/(हानि) प्रति मी. टन (रु.)
2001-2002	100	100	(100)
2002-2003	83	104	247
2003-2004	65	92	145
2004-2005	65	85	(352)
जांच अवधि (वार्षिकीकृत)	58	85	(155)

106. यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री में काफी घाटा हुआ है और वह लाभ की स्थिति की तरफ से वित्तीय घाटे की स्थिति की ओर चला गया जैसाकि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में गिरावट से देखा जा सकता है।

(ख) रोजगार और मजदूरी पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

107. जहाँ तक रोजगार और मजदूरी का संबंध है, घरेलू उद्योग को क्षति के संकेतक के रूप में रोजगार स्तर में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक ही संयंत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करता है और विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई अनन्य कर्मचारी शक्ति नहीं है। कंपनी का समग्र रोजगार और मजदूरी परिदृश्य दर्शाता है कि कर्मचारियों की संख्या में गिरावट हुई है जबकि मजदूरी पर किए गए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष	कर्मचारियों की सं.	मजदूरी (लाख रु.)
2001-2002	100	100
2002-2003	100	31
2003-2004	99	37



2004-2005	95	44
जांच अवधि (वार्षिक)	93	45

### ग. उत्पादकता पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

108. इकाई के कुल द्रव उत्पादन के संदर्भ में श्रम उत्पादकता दर्शाती है कि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

वर्ष	कुल उत्पादन (सभी द्रव) कि. ग्रा.	कर्मचारियों की सं.	उत्पादकता कि. ग्रा.
2001-02	****	100	100
2002-03	****	100	145
2003-04	****	99	168
2004-05	****	95	178
जांच अवधि (वार्षिक)	****	93	216

109. तथापि, उत्पादकता में सुधार हेतु उद्योग की लाभप्रदता के रूप में रूपांतरित नहीं हुआ है। यह पाया गया कि जबकि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे उत्पादन की इकाई लागत को घटाने में मदद मिली तब भी घरेलू उद्योग के लाभ बिक्री कीमत में गिरावट के कारण लाभ की स्थिति से काफी नीचे आ गए।

### (घ) नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव और लगाई गई पूंजी पर आय

विटामिन ए पामिटेड	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू बिक्री पर लाभ	(****)	****	****	(****)	(****)
प्रवृत्ति	(100)	646	372	(494)	(754)
नकद प्रवाह स्थानीय उत्पादन	****	****	****	****	****
नकद प्रवाह रू. प्रति मी. टन स्थानीय के लिए	****	****	****	****	****
लगाई गई पूंजी (लाख रू. में)	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	212	248	280	322
लगाई गई पूंजी पर आय (%)	(****)	****	****	(****)	(****)
प्रवृत्ति	(100)	305	93	(741)	(696)

110. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि नकद प्रवाह और लगाई गई पूंजी पर आय में विजयवारी अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि के पश्चात गिरावट आई।

## (ड.) भण्डार सूची

111. घरेलू उद्योग की स्टॉक की स्थिति की जांच यह प्रदर्शित करती है कि आबद्ध खपत और निर्यात बिक्री में वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के अंत में घरेलू उद्योग के स्टॉक में वृद्धि हुई।

वर्ष	प्रारम्भिक स्टॉक मी. टन	अंतिम स्टॉक मी. टन
2001-2002	100	100
2002-2003	0	13900
2003-2004	13900	2100
2004-2005	2100	300
जांच अवधि वार्षिक	300	2200

## (च) वृद्धि

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि मांग में स्वस्थ वृद्धि हुई है तथापि उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय जैसे मानदण्डों के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र गिरावट आई है।

## (छ) नए निवेश प्राप्त करने की क्षमता

113. निर्यातकों ने दलील दी है कि घरेलू उद्योग को किसी निवेश संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और वस्तुतः वह अधिग्रहण का आनंद उठा रही है। अतः उनकी नए निवेश प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु में नए निवेश नहीं किए हैं। घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में उल्लेखनीय कमी आई है जिससे नए निवेश प्राप्त करने की इसकी भावी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।

## (ज) पाटन मार्जिन का स्तर

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के संकेतक के रूप में संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन उल्लेखनीय और न्यूनतम सीमा से ऊपर पाया गया है।

## छ.3.4 समग्र मूल्यांकन

115. कारकों का उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू बाजार में अच्छी मांग, उत्पादकता में सुधार और पिछले वर्षों की तुलना में इसकी उत्पादन लागत में कमी के बावजूद, उद्योग उत्पादन में गिरावट, और बिक्री, कम निवल बिक्री वसूली, उच्चतर भण्डार सूची, निवेश और लाभ पर नकारात्मक या कम आय के कारण क्षति का सामना कर रहा है। क्षति जिसको वहन किया जा रहा है वास्तविक और काफी है। अतः हितबद्ध

पक्षकारों की दलीलें कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है, प्रमाणिक नहीं है।

#### उ.4 कारणात्मक संबंध

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलीलें दी हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध देशों से आयातों से इतर कारकों द्वारा हुई है। यह दलील दी गई है कि औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ) के तहत निर्धारित की गई कीमत वह उच्चतम सीमा है जिस पर आयातित वस्तुएं घरेलू बाजार में बेची जा सकती हैं। अतः भारतीय उपभोक्ताओं को उनकी कीमतें और उनके निर्यातों का पहुँच मूल्य भी डी पी सी ओ कीमत द्वारा निर्देशित किया जाता है। घरेलू उद्योग भी अपनी वस्तुएं डी पी सी ओ कीमत के करीब बेच रहा है और इसकी उच्चतर लागत के कारण क्षति, यदि कोई हो, जिसका सामना घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है, को संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं बताया जा सकता।

117. यह दलील भी दी गई है कि डी पी सी ओ कीमत के अंतिम उपभोक्ता को बिक्री कीमत होने के कारण उनकी निर्यात कीमत पुनर्विक्रेता के मार्जिन का ख्याल रखती है। अतः प्राधिकारी को क्षति मार्जिन की गणना डी पी सी ओ कीमत के आधार पर करना चाहिए न कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई एन आई पी, यदि कोई हो, के आधार पर।

118. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच मूल्य डी पी सी ओ कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है मले ही पुनर्विक्रेता के मार्जिन हेतु मामूली मार्जिन को रखा जाए।

119. पूर्ववर्ती खण्ड में वास्तविक क्षति की विद्यमानता और घरेलू उद्योग की कीमतों पर इसके कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत मंदी और न्यूनता संबंधी प्रभावों के रूप में पाटित आयातों के मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों की पुष्टि की गई है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गैर आरोपण के मुद्दे की जांच करने से पहले अनिवार्य कारकों की निम्नानुसार जांच की गई है:-

(क) तीसरे देशों से आयात:- उन देशों जो जांचाधीन नहीं हैं, से आयात या तो नगण्य है क्योंकि उनमें से कुछ नमूना बिक्री प्रतीत होते हैं न कि वाणिज्यिक बिक्री, या संबद्ध देशों से पाटित कीमतों से उच्चतर कीमतों पर हैं और इसलिए, घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं करते हैं। पाटित आयात जांच अवधि के दौरान कुल आयातों का 94 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

(ख) मांग में कमी:- संबद्ध वस्तु के लिए मांग में क्षति जांच अवधि के दौरान ठोस रूप से वृद्धि हुई है। इसलिए मांग में संभावित कमी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

(ग) खपत का तरीका:- खपत के तरीके में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का आरोप किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं लगाया गया है।

(घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें :- वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि अन्य व्यवहार्य उत्पादकों ने या तो उल्लेखनीय उत्पादन करना बंद कर दिया है या संबद्ध वस्तु के व्यापारी को बदल दिया है। इसलिए, घरेलू प्रतिस्पर्धा को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का कोई साक्ष्य प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

(ङ) प्रौद्योगिकी का विकास:- प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके। तथापि, प्रौद्योगिकीय अंतर के कारण घरेलू उद्योग को लागत संबंधी हानि का कोई दावा नहीं किया गया है।

(च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन :-

निर्यात	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	अप्रैल, 2004-सितम्बर
मी. टन	-	-	****	****	****

घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री वास्तविक है और इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित होती है। किन्तु निर्यात से लाभप्रदता नकारात्मक है। हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि निर्यात निष्पादन और इसकी निर्यात बिक्री से कमतर वस्तु ने वस्तुतः घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन की क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्री संबद्ध देशों से और आयातों के संबंध में घरेलू और निर्यात बाजारों में कीमतों और लाभप्रदताओं को पृथक-पृथक करके जांच की गई है। इसलिए, कंपनी के निर्यात निष्पादन के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, को पाटित आयातों के कारण नहीं माना जा सकता। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क प्रामाणिक नहीं हैं।

(छ) उत्पादकता:- घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कुल उत्पादन और उत्पादकता प्रति कर्मचारी के रूप में वृद्धि हुई है। अतः इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

120. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों की इन दलीलों का संबंध है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति सरकारी कीमत और कर संबंधी नीतियों के कारण हुई है और इसका पाटित आयातों से कोई लेना-देना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात का पहुँच मूल्य डीपीसीओ कीमत से काफी कम है भले ही पुनर्विक्रेता के लिए तर्कसंगत मार्जिन पर विचार किया जाए जिससे यह संकेत मिलता है कि चाहे डीपीसीओ कीमत को बेचमार्क के रूप में लिया जाए, पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर उल्लेखनीय क्षतिकारी प्रभाव है। अतः निर्यातकों की दलील कि सरकारी नीतियाँ और डीपीसीओ कीमतें क्षति का एकमात्र कारण हैं, प्रामाणिक नहीं है।

### उ.5 कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

121. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच प्रदर्शित करती है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से वास्तविक रूप से गिरावट आई। पाटित आयात कीमतें और इसके फलस्वरूप संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई। कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री की निरपेक्ष मात्रा में कमी आई है। यह भी देखा जाता है कि यद्यपि डीपीसीओ कीमत ने भी घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन की लागत की वसूली करने के लिए अपनी कीमत में वृद्धि करने से सेवन तथापि पाटित आयातों के कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री मात्रा में वृद्धि करने और घरेलू बाजार में एक बहुत अच्छी मांग की स्थिति के बावजूद अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने से रोक रखा।

122. उपर्युक्त गैर-आरोपण विशेषण दर्शाता है कि यद्यपि अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया होगा तथापि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने, उनकी मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति पहुंचाई है। संबद्ध देशों से ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति उल्लेखनीय और वास्तविक है।

123. उपर्युक्त गैर-आरोपण विशेषण दर्शाता है कि यद्यपि अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया होगा तथापि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने, उनकी मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति पहुंचाई है।

124. इसलिए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के साथ-साथ उपर्युक्त चर्चा किए गए कारकों द्वारा हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति उल्लेखनीय और वास्तविक है।

### ज. क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण

125. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत को जांच अवधि के दौरान उत्पादन की लागत और घरेलू उत्पादक की अन्य संबंधित लागतों पर ध्यान देकर रिलायंस उद्योग विरुद्ध निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है जो विटामिन ए पामिटेड 1.7 एमआईयू/ग्राम के 4301.03 रु./कि.ग्रा. बनती है।

126. घरेलू उद्योग ने अपने पञ्च-प्रकटन अभ्यावेदनों में यह टिप्पणी की है कि प्राधिकारी द्वारा किया गया एनआईपी निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप नहीं है और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसे औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत किए गए अधिदेश के अनुसार विधिवत् रूप से सत्यापित और लेखा परिक्षित किया गया है, को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तत्वावधान में बनाए गए सरकारी संगठन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को प्रस्तुत किया गया था। यह दलील दी गई है एनपीपीए, माननीय घरेलू प्राधिकारी द्वारा परिकलित 22% की तुलना में 26% के उचित

प्रतिफल हेतु अनुमति देता है। इन कारकों से क्षति सहित कीमतें स्पष्टतः नीचे आ जाती हैं। घरेलू उद्योग ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि के दौरान एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ उच्चतम कीमत स्तर वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर बढ़कर 4564.50 रु. प्रतिकिग्रा. हो गई है। किन्तु इसी अवधि के लिए तय की गई क्षतिरहित कीमत एनपीपीए द्वारा तय किए गए कीमत स्तर से काफी कम है।

127. घरेलू उद्योग ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि अप्रैल से जून, 2007 की अवधि के लिए अद्यतन आयात आंकड़ों के अनुसार, चीन जन.गण और स्विटजरलैंड से संबंधित उत्पाद का आयात दर्शाता है कि वे कीमतों का नीचे की ओर समायोजन कर रहे हैं और इस प्रकार प्रारंभिक शुल्कों को अवशोषित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में संबद्ध देशों विशेषकर चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं की कीमतें उन कीमतों जिन पर उनका जांच अवधि के दौरान आयात किया जा रहा था, की तुलना में आगे और कम की जा रही हैं। स्पष्टतः घरेलू भारतीय बाजार में कीमत प्रभाव अभी भी महसूस किया जा रहा है जिसके कारण निर्यात कीमत में अब प्रारंभिक शुल्क को आमेलित करने के लिए भारी कमी की गई है तथा मूल जांच अवधि के बाद सीमाशुल्क में कमी तथा भारतीय रुपए की मजबूती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

128. घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए शुल्क की सिफारिश उनकी लागत के आंकड़ों को हिसाब में लेते हुए निकाली गई एनआईपी के आधार पर की जानी चाहिए न कि प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई संगणना के आधार पर। तथापि, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए उच्चतर एनआईपी आंकड़ों को स्वीकार नहीं करते हैं और डीपीसीओ कीमत अपनाते हैं तो उन्हें वित्त वर्ष 2005-06 के आंकड़ों के आधार पर 27.3.2007 से लागू संशोधित डीपीसीओ आंकड़ों पर विचार करना चाहिए जो वर्तमान जांच में जांच अवधि से मेल खाते हों।

129. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चूंकि डीपीसीओ कीमत भारत में बिक्री की अधिकतम कीमत है इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के निर्धारण हेतु इस कीमत को ध्यान में रखना चाहिए और क्षति जांच अवधि के दौरान डीपीसीओ कीमत के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया है कि डीपीसीओ कीमत भारत में बिक्री की अधिकतम कीमत होने के कारण पुनर्विक्रेता के लाभ हेतु तुलना पर विचार किया जाना चाहिए। इसके समर्थन में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद पुनर्विक्रेता की कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की गई है जिसे पूर्व में उल्लिखित कारणों से रिकार्ड में नहीं लिया जा सका।

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन निर्यातकों के निर्यात सौदे सीधे ग्राहकों और पुनर्विक्रेताओं को होते हैं। आयातकों ने पुनर्बिक्री कीमत तथा ऐसे आयतों पर उनके द्वारा किए गए एसजीए व्यय अथवा अर्जित लाभ के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अतः प्राधिकारी क्षति मार्जिन की तुलना और निर्धारण के प्रयोजनार्थ डीपीसीओ कीमत पर पुनर्विक्रेता के लाभ मार्जिन हेतु ऐसी छूट देने में कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

131. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में एनआईपी का निर्धारण प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। विटामिन ए पामिटेड 1.7

एमआईयू/ग्राम के लिए एनआईपी का निर्धारण 4304.03 रु. प्रति कि.ग्रा. किसानों है 4.27.3.2007 से एनपीए द्वारा निर्धारण मौजूदा डीपीसीओ कीमत 4564.50 रु./कि.ग्रा. है जिसे 2005-06 की अवधि के लिए लागत के आंकड़ों के आधार पर तय किया माना जाता है। प्राधिकारी द्वारा जिस अवधि के लिए आंकड़ों की जांच की गई है उस अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 से 30 सितम्बर, 2005 तक के 18 माहों में अप्रैल, 2005- मार्च, 2006 के लिए एनपीए द्वारा जांच किए गए 12 माह के आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त अन्तर है। इसके अलावा, एनपीपीए तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्राप्ति की दर स्पष्टतः अलग- अलग है। अतः क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु डीपीसीओ के तहत एनपीपीए की वर्तमान कीमत को अप्रत्यक्ष उचित नहीं होगा। इसी तर्क के आधार पर इस मामले में क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु पूर्ववर्ती अवधि की एनपीपीए कीमत भी उचित नहीं होगी। अतः क्षति मार्जिन निकालने के लिए प्राधिकारी ने उपर्युक्तानुसार निर्धारित एनआईपी की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है।

132. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान डीपीसीओ अधिकतम कीमत से वह अधिकतम कीमत तय हुई थी जिस पर घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री कर सकता था। अतः अहेतुक मानकों के अनुसार इस अधिकतम कीमत के कारण घरेलू उद्योग को हो सकने वाली क्षति, यदि कोई हो, का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता और पाटित आयातों के क्षति मार्जिन को जांच अवधि के दौरान प्रचलित डीपीसीओ कीमत से कम पर हुए पाटित आयातों की मात्रा तक सीमित किया जा सकता है। तदनुसार, पाटित आयातों के लिए जिस क्षति मार्जिन को आधार माना जा सकता है वह निम्नानुसार बनता है :

देश	निर्यातक	एनआईपी	एलवी	जांच अवधि के दौरान डीपीसीओ कीमत	क्षति मार्जिन	पाटित आयातों के कारण हुई क्षति	पाटित आयातों के कारण हुई क्षति
		रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	%
स्विट्जरलैण्ड	डीएसएम न्यूट्रिशनल उत्पाद	*****	*****	4125.9	*****	*****	5-15%
स्विट्जरलैण्ड	अन्य सभी	*****	*****	4125.9	*****	*****	15-25%
चीन जन. गण.	सिनकेम के साथ एनएचयू	*****	*****	4125.9	*****	*****	10-20%
चीन जन. गण.	अन्य सभी	*****	*****	4125.9	*****	*****	25-35%

### अ. निष्कर्ष

133. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिसर में यथाप्रस्तुत प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का प्रवेश निर्यातक देशों के घरेलू बाजार में उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है;

- (ii) संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन काफी अधिक है तथा न्यूनतम सीमा से ज्यादा है;
- (iii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और
- (iv) घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव के साथ-साथ अन्य कारकों, दोनों के कारण हुई है।

#### भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

#### ट. सिफारिशें

135. निर्धारित नियमों के अनुसार पाटन, क्षति तथा पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच शुरू और पूर्ण करने के बाद तथा संबद्ध देशों के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरान्त प्राधिकारी का मत यह है कि पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समायोजित करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी नीचे उल्लिखित रूप में और ढंग से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

136. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से कमतर राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि चीन जन. गण. और जापान मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए जिसकी वसूली अंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से अनिश्चित काल तक की जाए। पाटनरोधी शुल्क इसके साथ संलग्न शुल्क तालिका के कालम सं. 9 में उल्लिखित राशि होगी।

137. पूर्वोक्त के अधीन 23 फरवरी, 2007 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित अनंतिम जांच परिणामों की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

#### ठ. आगे की प्रक्रिया

138. केन्द्र सरकार के उक्त आदेशों के खिलाफ कोई अपील, जो इस सिफारिश के कारण उत्पन्न होती हो, अधिनियम के संगत उपबन्धों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।



139. प्राधिकारी समय-समय पर यथा संस्तुत निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें समाप्त करने की समीक्षा इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार कर सकते हैं। ऐसे किसी समीक्षा के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक इसे किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत न किया जाए।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	293621	विटामिन-ए पामिटेट	कोई	स्विट्जरलैण्ड	कोई	डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स एजी स्विट्जरलैण्ड	डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स एशिया पैसिफिक प्रा. लि., सिंगापुर	313	कि. ग्रा.	रु.
2	-वही-	-वही-	कोई	स्विट्जरलैण्ड	चीन से इतर कोई अन्य	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	कोई	069	कि. ग्रा.	रु.
3	-वही-	-वही-	कोई	चीन से इतर कोई अन्य	स्विट्जरलैण्ड	कोई	कोई	690	कि. ग्रा.	रु.
4	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन. गण.	कोई	झेजियांग एनएचयू कंपनी लि.	सिनकेम इंटरनेशनल क. लि.	590	कि. ग्रा.	रु.
5	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन. गण.	कोई	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	कोई	941	कि. ग्रा.	रु.
6	-वही-	-वही-	कोई	कोई	चीन जन. गण.	कोई	कोई	941	कि. ग्रा.	रु.

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2007

**Final Findings****Sub: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from Switzerland and China PR**

**No. 14/11/2005-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof:

2. WHEREAS on the basis of an application filed by M/s. Nicolas Piramal India Ltd. (herein after referred to as the Applicant) the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Act and Rules made there under, issued a public notice dated 23<sup>rd</sup> March, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations into alleged dumping of Vitamin A Palmitate (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from Switzerland and China PR (herein after referred to as subject countries).

3. The Authority notified its Preliminary findings vide Notification dated 20<sup>th</sup> February 2007 recommending provisional antidumping duty on import of subject goods from the subject countries and acting upon such recommendations of the Authority, the Department of Revenue, vide its notification No.47/2007-CUSTOMS dated 28<sup>th</sup> March, 2007, imposed provisional antidumping duty on the subject goods.

**A. Procedure**

4. Procedure described below has been followed with regard to this investigation after issuance of the public notice notifying the preliminary findings of the Authority.

- (i) The Designated Authority sent copies of preliminary findings dated 20<sup>th</sup> February 2007 to all known interested parties including, the responding exporters, importers and users of the subject goods, Embassies of the subject countries in India, and the domestic industry and invited the comments of the interested parties on the preliminary findings. Parties to this investigation were requested to make their views known in writing within 40 days of the notification of the preliminary findings.
- (ii) The comments of the interested parties in response to the preliminary findings have been taken on record and the Authority has examined the issues raised therein in this disclosure statement.
- (iii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

- (iv) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India was worked out based on the information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.
- (v) The Authority held a public hearing on 09.04.2007 to provide an opportunity to all interested parties to present their view. Oral submissions made by the parties during the public hearing reproduced in writing have been taken on record for the purpose of this investigation.
- (vi) Confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential \*\*\* in this finding represents information furnished by the domestic industry on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (vii) The essential facts of the case were disclosed to all interested parties in the form of confidential and general disclosures on 24<sup>th</sup> August 2007. Comments of the interested parties on the disclosure statement, to the extent they are relevant and supported by evidence, have been considered by the Authority.
- (viii) Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> April 2004 to 30<sup>th</sup> September 2005 (POI).
- (ix) For the sake of brevity the comments of interested parties and issues raised prior to the preliminary findings and addressed therein have not been repeated in this finding.

### **C. Product under Consideration and Like Article**

5. As recorded in the Preliminary Findings, the product involved in the current investigation is Vitamin A Palmitate. Vitamin Palmitate is manufactured in various strengths and forms and due to technical and commercial substitutability of these grades Vitamin-A Palmitate of all concentrations and forms were included within the product under consideration. However, the responding exporters from the subject countries have raised certain issues on the scope of the product under consideration, which have been examined as follows.

#### **C.1 Views of the exporters and other interested parties**

6. The exporters from China, in their post preliminary finding comments, have submitted that while defining the scope of products concerned, the Designated Authority has only used overall product as the criterion and did not apply its mind in respect of the significant differences in respect of products/grades /uses and market segments. Therefore, the Authority should exclude these products/grades that have not faced any injurious dumping during the POI and to limit the scope of investigation. It has been argued that Vitamin- A Palmitate 1.0 MIU/Gm has not been imported during the POI and grade 1.7 and grade 1.0 are not commercial substitutes. It has been further argued that apart

from some differences in prices, the demand for each type of Vitamina A is based on end-user requirements and preferences and convenience and the market segments served, the distribution channels. It has been argued that levels of trade between domestic goods and goods exported by the responding exporters from China are substantially different and there is limited competition between them. Referring to the website information of the domestic industry the exporters have argued that the domestic industry clearly sets out at least 9 distinct products/forms of the grade 1.7 alone and the users, market segments and patterns of consumption of different grades/forms of the Subject Goods are different. Therefore, various forms and concentration of Vitamin-A Palmitates manufactured by the domestic industry and exported from China are not technically and commercially substitutable and hence should not be covered under the product under consideration and like articles.

7. The exporter from Switzerland in its submissions has submitted that there is no other product, other than Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm, exported from Switzerland during the POI. Therefore, all other Vitamin A products are required to be excluded from the purview of the product under consideration.

### **C.2 Views of the Domestic Industry**

8. The domestic industry, in its submissions, has argued that "Vitamin A Palmitate" is available in various strengths viz., Vitamin A Palmitate 1.7; and Vitamin A Palmitate 1.0. Since Vitamin A Palmitates of various strengths have the same end use, the present investigations should cover the subject goods in all its strengths and forms. Though the subject goods are imported at present only in 1.7 MIU/g strength, the imports do affect the sales of both 1.7 MIU/g and 1.0 MIU/g as these grades can be used interchangeably by the user industry. It has been argued that availability of higher strength at lower prices proportionately reduces the per unit price of lower strength and as such the user prefers to buy higher strength in order to reduce its cost. Hence, the Authority should consider the imposition of anti dumping duty also on Vitamin A Palmitate on a MIU/g basis, which can be increased or decreased proportionately depending upon the higher or lower strength of the subject goods. It is also submitted that this was done by the Hon'ble Designated Authority in the earlier investigation covering the subject goods imported or originating from EU, Singapore and Georgia. Therefore, this issue has already been settled and confirmed by this Authority in the final findings and the mid term review investigation conducted thereafter.

9. On the issue of the uses of the grades in question, the domestic industry has clarified that primarily the same are used in the human nutrition by way of food and pharma products (including the Unicef programme) along with some usage in the cosmetic products. As regards the feed grade is concerned, it has been clarified that Vitamin A Palmitate Grade 1.6 is the feed grade used for animal consumption and the same is not covered in the product under consideration.

### **C.3 Examination by the Authority**

10. Technical literatures of various manufacturers indicate that Vitamin A Palmitate is an orange yellow to yellowish red oily liquid, which may crystallize

below 20 C. It contains a mixture of Vitamin A Palmitate and Vitamin A Acetate, having a content of not less than 90% Vitamin A Palmitate and not more than 10% Vitamin A Acetate. Vitamin A Acetate is present on account of the chemical process of manufacture. It contains BHA and BHT as anti oxidants. Vitamin-A Palmitate is produced in various concentrations/potencies, primarily as 1.7 MIU/Gm and 1.0 MIU/Gm, which are used in pharmaceutical, cosmetic and food supplement applications. It has been clarified by the domestic industry that Vitamin A Palmitate Grade 1.6 is the feed grade, used for animal consumption, and the same is not covered in the product under consideration.

11. The submissions of the exporters also indicate that Vitamin A Palmitate 1.7M MIU/g is a greenish yellow to golden yellow, oily liquid that may crystallize on storage. It consists of pure vitamin A Palmitate. Other forms of Vitamin A Palmitate can contain an antioxidant, either BHA/BHT or in some cases Tocopherol. Vitamin A 1.0 MIU/gm is also a greenish yellow to golden yellow, oily liquid that may crystallize on storage. It consists of Vitamin A Palmitate in peanut oil. It contains either Tocopherol or BHA/BHT as antioxidants. The basic difference between there two types of Vitamin A Palmitates is in the strength/potency. All forms of A Palmitate 1.7 are of the same potency but the other part of their product description refers to the antioxidant that is a part of the formulation (this is something that makes the form more stable). Same applies to 1.0 MIU/gm. All forms can be used for food, pharmaceutical and cosmetic preparations. The production process, physical and chemical characteristics of both the products are similar and the products are substitutable and can be interchangeably used. The Authority also notes that DPCO combines both Vitamin A Palmitate 1.7 and 1.0 under single category for fixation of ceiling price. It has been brought to the notice of the Authority that the products can be interchangeably obtained by altering the strength merely by dilution.

12. The above examination clearly establishes that Vitamin A Palmitates of different concentrations i.e., 1.7 MIU/Gm and 1.0 MIU/Gm are merely product sub-types rather than separate products themselves, as has been argued by the exporters. These product types are technically and commercially substitutable. Had these been two distinct products the arguments of the interested parties for exclusion of the product not imported during the POI would have held ground. One particular types (1.7 MIU) has been imported during the POI and if the duty is imposed on this type while excluding the other type from duty, the duty could be easily circumvented by importing the excluded category which can substitute the dutiable goods. Therefore, merely because a product sub-types have not been imported during a particular time would not enable it to be excluded from the scope of product under consideration which covers all product subtypes that are technically and commercially substitutable.

13. In their post disclosure submissions the interested parties have reiterated their arguments for exclusion of Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm from the scope of product under consideration on the grounds that this product has not been imported during the POI. In support of their argument they have quoted the certain CESTAT rulings in which the Hon'ble Tribunal held that an article which has not been exported to India cannot, be subjected to imposition of anti-dumping duty under Section 9A(1) of the Act.

14. The Authority notes the above arguments of the interested parties in their comments to the disclosure statement. The Article under investigation refers to the article/product as a whole and not to any of its subtypes or models or specifications. As noted earlier Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm are product subtypes having same end use, differing only in concentration. Therefore, duty on Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/gm could lead to circumvention of duty through import of Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/gm which has same end use. Whereas Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm has a totally different end use for animal feed and hence does not fall within the scope of the product under consideration. Therefore, the arguments of the interested parties cannot be sustained.

15. In view of the above the Authority holds that the product under consideration has been correctly defined as Vitamin A Palmitate, which would cover both 1.7 MIU and 1.0 MIU. However, the product under consideration would not cover 1.6 MIU as it has been clarified to be a different product with a different end use. Accordingly, the product under consideration is defined as Vitamin A Palmitate, which covers Vitamin A Palmitate 1.7MIU/gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/gm (herein after termed as the "subject goods") in all its strengths and forms.

16. The product is classified under heading No. 293621.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **D. Standing of the Domestic Industry and initiation of the investigation**

17. The application has been filed by M/s Nicolas Piramal India Ltd. The applicant is the sole known producer of subject goods in India and accounts for complete production of subject goods in India. The petitioner, therefore, satisfies the standing to file the present petition and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

#### **E. Other submissions and issues raised:**

18. As recorded in the preliminary findings the importer of the subject goods in India, M/s Hexagon Nutrition Pvt. Ltd., in its submission, has argued that Switzerland has maintained its price level of US\$70/- per Kg in the last 3 years, whereas China has reduced its price from US\$66/- to the current export price of US\$56/-. They have also argued that Nicholas Piramal has exported the subject goods at a price much lower than the price at which the subject goods have been exported from Switzerland.

19. They have further argued that cost effective availability of this product is essential as several charitable organizations are funding projects in India for vitamin supplements to fight wide spread vitamin deficiency. Imposition of ADD would lead to monopolizing situation for NPIL and the consumers have to bear the burden of higher price due to antidumping duty.

20. M/s DSM Nutritional Products (DNP), has reiterated its arguments that DNP does not pursue a policy of dumping its products on the Indian market and no material injury is caused to the domestic industry on account of their exports to India. It has been argued that the purchasing powers and market structures, in Switzerland and in India, are entirely different, as are the volumes of products sold per transaction – an element that has a direct effect on sales price. They have argued that sales to the EU market more closely resemble the characteristics of the export sales to India than sales to the Swiss market, and the prices that can be achieved in that market are comparable as well. It has been further submitted that imposition of an anti-dumping duty on imported products from Switzerland would lead to recreating the monopoly in India that the Petitioner was able to establish for itself in 2003 and the first half of 2004 following the imposition of duties on imported products from Singapore, Georgia and the EU. This will inevitably result in higher sales prices to Indian customers and harm the Indian economy.

### **E.1 Confidentiality issues**

21. In addition to their comments on various aspects of the case both, the domestic industry, as well as the exporters participating in this investigation, has raised the issue of excessive confidentiality claimed by the other interested parties. As far as the issue of confidentiality and insufficient non-confidential disclosure of information by the parties to the investigation is concerned, the issues raised have been examined. The Authority notes that to the extent possible and practicable the confidentiality claims of various parties submitting the information have been examined and confidentiality claims admitted on the basis of nature of information provided by the parties. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties' alongwith non-confidential summary thereof, have been treated confidential.

22. The domestic industry in its comments to the disclosure statement has argued that the participating exporters from Switzerland and China PR should be declared non-cooperative and dumping margins should be determined on facts available basis because of the fact that these exporters have not placed complete facts before the Authority in terms of the standards set. They have also raised the issue of insufficiency of non-confidential disclosures by these parties.

23. In this connection the Authority notes that the degree and extent of cooperation and information submitted by the participating exporters, as well as non-confidentiality issues have been adequately examined and the submissions filed by these exporters have been accepted though certain claims made these exporters have not been accepted by the Authority. Authority also notes that non-acceptance of certain claims or rejection of certain information by the Authority does not render the exporter concern non-cooperative or attract best information available clause.

**F. Determination of Dumping and Dumping Margins****F.1 China PR**

24. The Authority, noted in its preliminary findings that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by WTO members such as EU and USA and therefore, in terms of para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules China PR was treated as a non-market economy country for the purpose of provisional assessment of the normal value.

25. Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended provides that the presumption of non-market economy against a country can be rebutted by individual exporters for individual treatment if the exporter(s) from such country provide information and sufficient evidence, on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China were asked to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

26. Only one Manufacture of the subject goods in China i.e., M/s Zhejiang NHU Company Limited (NHU), and its related exporter M/s Synchem International Co. Ltd. have filed their questionnaire response and Market Economy Questionnaire response claiming market economy status and individual treatment. The views of the interested parties on the market economy claim of the producer/exporter from China are as follows:

**F.1.1 Views of Domestic Industry**

27. In its various submissions commenting upon the market economy claims of the Chinese exporters the domestic industry has inter alia argued that:



- As per the Company's information published in their own website, the Company was established after the reorganization of the former Xinchang Chemical Company which was founded in November, 1988 and has now developed into a state-level hi-tech enterprise. Such being the case, it is required to be established by them that the ownership of such plant has been transferred to private parties on the basis of market price and was not influenced with the erstwhile non market economy system. Para 8 (3) (b) also requires the Authority to examine whether the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortion carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payments via compensation of debts. Therefore, it is essential to examine the process of transformation and how the assets and liabilities of the entity have been valued for the purpose of the privatization. Hence the argument of the exporter that the Authority cannot look beyond the period of investigation to find the status and the process of privatization is not tenable. Thus, whether the price at which the plant was sold was according to the market principles, requires investigation. Also, the shareholders who invested in the share capital and their relationship with any of the related companies or the States also requires to be verified.
- As per the information available in the public domain the earlier company Xinchang Chemical Company had been one of the approved companies recognized by the Ministry of Science and Technology of PRC as one of the important new and high tech enterprises in National Torch Plan. The Torch Programme is a national plan that was implemented in August 1988 with the State Councils approval. It aims to propel regional economic growth through developing high-tech industries. It also helped cultivate thousands of high-tech firms and 53 high-tech zones, and develop patented products which have reached world advanced levels. The Central Science and Education Leading Group, since it was highlighted in March at the National People's Congress, had decided to invest 7 billion yuan (US \$ 843 million) within the next three years to try a knowledge and technology innovation project in the Chinese Academy of Sciences.
- The domestic industry has also argued that as per the information available on Torch Plan in the public domain, the same is said to be a subsidy as defined under the WTO Agreement as it is a financial contribution made by the Government body and has been made available to specific entities such as Xinchang Chemical Company. It has also been argued that while under the SCM Agreement, an actions can be instituted against China as regards countervailing duties is concerned, in the facts of the present case the contribution is subsumed in the cost of production and financial benefits which have been conferred on the Company and therefore, the principles of MET cannot said to have been met.

- It has also been argued by the domestic industry that the producer is also recognized to obtain supporting policies under the Brand Name Policy implemented for 2 years starting 26.1.2005 (which is during the Period of Investigation) specifically for improving export competitiveness and this producer has been specifically named as one of the companies to receive the said benefits conferred under this program.
- Further, the Producer has not even disclosed has an affiliate company in US with the name of China Vitamins LLC., based in New Jersey in the US. The MET Questionnaire clearly requires the producer to give specific information as to the companies which are related to the producer. This information too has not been disclosed by the producer anywhere in the responses filed.
- In its post disclosure submissions the domestic industry has argued that the profit margins etc. of the intermediaries involved in the export transactions to India should be adequately deducted to arrive at the export price;

**F.12 M/s Zhejiang NHU Company Limited (NHU), China PR and M/s Synchem International Co. Ltd.**

28. The exporter from China PR in its submissions has refuted the arguments of the domestic industry in respect of its Market Economy claims. It has been claimed that NHU has no "US website", and it has not authorized anyone in the United States to disclose information regarding NHU or any of its related companies. NHU has disclosed all its related companies in its response to the MET questionnaire.

29. The exporter in its submission has argued that several leading economies and members of WTO have recognized China as a market economy and Designated Authority in India has also given market economy treatment to several Chinese exporters in the past. It has been further argued that in Annex 2a2 of the Chinese Protocol of Accession to WTO, China has transparently and in good faith listed out the business sectors and, even companies, that continue to be under state control or receive subsidies or where the Government plays a role in decisions, *inter alia*, including on price and which shall be reformed during the transitional period. It is submitted here that neither is Subject Goods identified in the said Annex 2A2 to the said Protocol as such a business sector under state control or influence, nor is the exporter or the producer named in the said annex 2a2. Therefore, there is, *prima facie*, no reasonable basis to assume that the said Subject Goods business sector in China operates as a NME. Therefore, it has been argued that NHU/SYNCEM may be excluded from being deemed to be operating under NME conditions and the information furnished by NHU/SYNCEM clearly shows that NHU/SYNCEM makes its business decisions exclusively in a manner of business in a market economy.

30. It has been further submitted that the laws introduced in China in recent years as applicable to this business sector and to NHU/SYNCEM are similar to the comparable laws in market economies and had begun to be enforced by the POI. It has been further argued that NHU does not enjoy a monopoly on Subject Goods production, trade or exports and that there is no State/Government control on pricing and costing of NHU. NHU purchase the raw materials and sell the finished products at market driven prices that are not regulated by the State/Government. It is submitted that the accounting system used by NHU/SYNCEM is consistent with international norms in a market economy. NHU/SYNCEM does not receive any subsidies other than permitted VAT reimbursement that are levied on domestic sales and purchases its foreign exchange through the authorized dealer bank. Further, there is no distortion of production costs and financial situation of the Producer as is clear from the Confidential Response and accompanying confidential information. It has been argued that the Producer has not converted former State assets, or distorted depreciation thereof, or engaged in barter trade or debt forgiveness or debt/equity swaps, or received the benefit of any write-off.

31. It has been submitted that NHU/SYNCEM is subject to China's laws and regulations with respect to bankruptcy and property respectively and the exchange rate is based on the market rate as determined by the Central Bank. NHU/SYNCEM has borrowed from the banks on market terms and repaid its loans as per schedule. As in a market economy NHU/SYNCEM has acquired its land through market economy mechanisms.

32. As far as the National Torch Programme is concerned, the exporter has argued that this programme is to promote development and application of high-tech products/process, which provide some marginal support to the covered product/process. This is a kind of program that is used by most, if not all, market economy WTO members, including India. In addition, the program has not transferred any financial contribution and/or benefit, whatsoever, within the meaning of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures to NHU, let alone in respect of the Subject Goods.

33. As far as the history and antecedents of the previous companies and holding companies the exporter has argued that information requested cannot be for an unspecified period and that neither the Questionnaire nor the NME Questionnaire, nor any letter to NHU/Synchem from the Hon'ble Authority, has specified a separate period for which information is sought other than the POI and period set out in the initiation notification. It has been argued that no question in the NME Questionnaire requests "history" of the cooperating party. Similarly, none of the four criteria of Market Economy provided in paragraph (3) of Article 8 in Schedule I to the said Rules specify unlimited "history". It is thus unfair and unreasonable to make a finding on the price structure of domestic sale of NHU and that of export to India of Synchem during the POI based on the legal

status of antecedents or "history" of the respondent 10-15 years ago, which should not have any impact on the normal value and/or comparability of the prices. It is also unfair and unreasonable to impose obligation of responding to this investigation to the shareholders of NHU.

### **F.1.3 Examination by the Authority**

34. The Authority has noted the arguments of the interested parties. M/s Zhejiang NHU Company Limited (NHU), China PR, alongwith M/s Synchem International Co. Ltd., has filed the exporter's questionnaire response and market economy questionnaire response. NHU is the producer of the subject goods in China and exports the same to India through its related company Synchem, which is a trading Company. NHU has claimed that it is a publicly listed company in China and major portion of its shares are held by a holding Company named, M/s Xinchang County Synthetic Chemicals Factory (Xinchang), and part of it is invested by public shareholders. The questionnaire response and Market Economy Response of the Company were examined and an on-spot investigation and verification was carried out in the premises of NHU and Synchem.

35. M/s. Zhejiang NHU Co. Ltd was established in 1998 as a limited liability Company under the Chinese Company Law. The Authority examined the antecedents of the responding Chinese Companies to find if the cost and prices of the producer has been significantly affected by state interference or carry over of distortions from earlier non-market economy system. Verification revealed that the production unit of NHU was earlier owned by Xinchang County Synthetic Chemical Factory. This factory was established in 1989 as a collectively owned enterprise under the prevalent collective enterprise system in the transition phase of Chinese enterprise law. However, verification revealed that the enterprise was initially invested by certain schools and school teachers in the Xinchang county. In 1994 the enterprise was incorporated as a 'collectively owned corporation' under the new Chinese Company Law.

36. Zhejiang NHU, the responding producer Company in this case, was established in 1998 as a new company limited by shares with major shareholding by Xinchang Chemical Factory and obtained the approval of the Zhejiang Provincial Government in 1999. The production unit of the M/s Xinchang Synthetic Chemical Factory was transferred to this unit as capital contribution of Xinxhang in NHU.

37. The assets of M/s Xinchang Synthetic Chemical Factory were appraised by M/s Xinchang Assets Appraisal Company in 1998 and as per the appraisal report the purpose of this appraisal was to set up a limited company by shares. The appraisal was carried out for the entire assets of the Company except the land. All of the net assets of Xinchang Synthetic were invested into NHU by the

former as a major promoter for the establishment of the company. However, the fixed assets of Xinchang in the form of land and building have not been transferred to the new entity and do not form a part of the capital of the new company. NHU became a public limited company in 2004 by way of issuance of ordinary shares to the general public. However, the original promoting enterprise i.e., Xinchang remains the major shareholder of this company. The Board of Directors of NHU is headed by Mr Hu Baifen, the chief promoter of Xinchang and other promoters are directors in the board.

38. During the verification certain issues in respect of financial support received by the Company under National Torch Programme and Brand Promotion Programme were also examined. A questionnaire was also sent to the Ministry of Commerce of Government of Peoples Republic of China with a request to provide certain information on these programmes and benefits, if any, received by the responding company in this case. A meeting was also held with the Chinese officials in MOFCOM. The MOFCOM has also filed a written reply to the said questionnaire. MOFCOM has submitted that subsidy issues are not relevant criterion for market economy status. However, these programmes and benefits accruing to the Company have been examined to see if these programmes have significant distorting effect on the cost and prices of the subject goods in the domestic market of the exporter concerned.

39. During the verification process and meetings with Chinese officials it was revealed that the National Torch programme was initiated in 1988 as a non-binding programme designed to promote industrialization of high-tech research and development (R&D) to facilitate local economic development. The Science and Technology Commissions at various levels of governmental agencies administered the programme. The subject product Vitamin was covered under the said programme. During the verification the Company confirmed that they are a beneficiary of the above programme and produced a copy of the certificate of July 2002. Verification certificate under the national Torch Programme was also produced which indicates that the entire investment for this product is self-financed. It was clarified by the Company that the entire project was implemented by the Company in its NHU plant and they have not received any contribution under the High Tech Industrial Development Area Scheme. Therefore, there is no contribution from the state to this Company under the above programme.

40. The Policy documents of this policy indicate that the following benefits are provided to the producers covered under the policy:

- a) Govt. support for obtaining funds from the banks for the products; Priority access to funds
- b) Fund support from the state also;
- c) Facilitates loans at lower interest rates;
- d) Entitles the beneficiaries for special grade credit from China Construction bank

Relevant extracts of the Annual Report of the administering agency for the programme for 2003 was produced by the company to claim that the subsidy component of the programme was negligible. Annual Report of National Torch programme 2003, a copy of which was produced for verification shows that total bank loans under this programme for all projects was 18.49 Billion RMB and subsidy element for 36 high tech project was 1.85 Billion RMB. The exporter, in its comments has submitted that these 36 high tech projects are 36 high tech development areas rather than specific products and bank loans were made at commercial terms. However, the policy document stated earlier does not support this argument.

41. As far as Brand Promotion Programme is concerned, this programme was initiated in 2005 by the Government of Peoples Republic of China. The programme is implemented by the Ministry of Commerce, National Committee of Reform and Development, Ministry of Finance and Ministry of Science and Technology. As per the clarification given by MOFCOM the objectives of the programme are to guide enterprises for brand-oriented approach, to strengthen quality control and R&D, to enhance product quality etc., mainly aimed at combating counterfeited products. The Company confirmed that they had received one time grant of RMB \*\*\*\*\* in 2005 for R&D development under this scheme for the company as a whole and not for any particular product.

42. As far as the status of Syncjem, i.e., the related exporter of NHU is concerned, the Authority notes that Synchem is a private limited liability company established in 1998 by way of investment by Xinchang Synthetic Chemical Factory, which is also the major shareholder of NHU; and one individual entrepreneur Mr Wu Tieping. Therefore, both the producer company (NHU) and the trading company (Synchem) are related and controlled by their major shareholding entity M/s Xinchang Synthetic Chemical Factory and would have the same status as of the main holding company (Xinchang). It is basically a trading company established in the Bonded Zone of Dalian to take advantage of the differential tax benefit available to the enterprises established in the bonded zones prior to 2001. However, this company basically acts as an external arm of NHU to procure orders and execute them while actual export documentation etc are done in the name of M/s NHU imports and Exports Company which holds the export licence for the product and is eligible for VAT refund benefit under the Chinese Law.

43. The producing Company, M/s NHU provided the list of major raw materials and utility suppliers and claimed that the raw material suppliers are private entities and not related to them. The list of suppliers of raw material and utilities is quite long and it was not possible to verify the antecedents of these suppliers. As far as power is concerned, the same has been procured from the state power producers.

44. The above examination indicates that the ownership status of the major share holders of NHU i.e., M/s Xinchang Synthetic Chemical Factory remains doubtful, because of the involvement of the schools and investments made through them in the holding Co. Therefore, controlling ownership of NHU and involvement of the State, in the form of capital investments through the schools, cannot be ruled out. The transfer of assets and liabilities of NHU from Xincheng to the new entities is also not transparent and does not appear to reflect the true market value. The assets transferred by the holding company also do not include the land and buildings and the value of such assets have not been taken into account in the capital assets of NHU. As far as the financial and infrastructure support of the Government to NHU and the product involved through National Torch Programme and Brand Policy of the Government are concerned, admittedly the Company has been benefited by these programmes though in a limited way. The Authority also notes that though this is not a subsidy investigation, the impact of such support on the cost and prices of the company would affect the normal value determination.

45. The Chinese producer/exporter, in its post disclosure submissions are argued that even if the Authority finds certain issues in respect of the evidence furnished for transformation of NHU and in respect also of the trivial subsidy program such issues cannot pass the "significance" test, to establish significant distortion. In this connection the Authority notes that the issue of carry over of distortions from the erstwhile non-market system has been addressed adequately in the foregoing paragraphs which establishes significant distortions in the cost of prices of the subject goods due to the nature of transformation and existence of state intervention through various policy instruments having direct impact on cost and prices.

46. In view of the above the Authority concludes that the cost and prices of the company are significantly distorted due to carry over of the distortions from the erstwhile non-market economy system and therefore, do not qualify for consideration for the purpose of determination of normal value of this company. Accordingly, the Authority proceeds to determine the normal value for this exporter in terms of para 7 of annexure I to the Rules.

**a) Normal Value**

47. Para 7 of Annex 1 to the Rules provides that

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country*

*shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, "keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time for selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

48. In the initiation notification the interested parties were intimated that the domestic industry had suggested that in view of non-market economy situation in China the European Union should be considered as the appropriate market economy third country for the purpose of determination of normal value in China. The Authority notes that there are only four major producers of the subject goods in the world out of which two are in the Europe, remaining two being in India and China. Therefore, considering the nature of the product and scale of sales of the product in Chinese and European markets, European Union would constitute an appropriate third country for the purpose of determination of normal value in China. The exporters from China, in their submissions have not commented on the proposal by the Hon'ble Authority to treat EU as comparison economy. However, it has been mentioned in the submissions that it is assumed therefore that the Hon'ble Authority is using EU as the comparison territory thereby concurring with the proposal of the Authority. Therefore, the Authority proceeds to determine the Normal Value in China in terms of para 7 referred above on the basis of selling price of the subject goods in the European Union.

49. The Authority notes that the selling prices of Vitamin-A Palmitate 1.7 MIU/gm, in the European market, are available for such a determination. The average selling price of Vitamin-A Palmitate 1.7 BHA/BHT in the European market during the POI was US\$ \*\*\*\*\* per KG at ex-factory level. The exports from China are of 1.7 MIU/Gms and a small quantity of 1.6 MIU/Gms. However, Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/Gm is not covered under the product under consideration as discussed earlier. Therefore, normal value in China PR has been determined based on the price in the European market which works out as US\$ \*\*\*\*\* per Kg of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gms.

**b) Export Prices**

**i) NHU-Synchem**

50. The exporter has exported 9900 Kgs of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/gm during the POI. However, NHU does not export the subject goods directly to India. It has a fully owned subsidiary M/s NHU Imports and Exports which functions as a division of NHU which handles the exports of this commodity



manufactured by NHU. However, as far as export to India is concerned, there is another intermediary company, M/s Synchem, which is a related company of NHU, which actually makes the exports to India. NHU first sales the goods to NHU Imports and Exports through an internal invoice and NHU Imports and Exports raises another invoice on M/s Synchem, which is a trading Company, located in Dalian Bonded Zone. Synchem raises the commercial invoice on the importer in India. The documentations for exports are actually back-to-back and show the name of NHU as the producer of the goods. However, there is a considerable difference in the invoice values of NHU, NHU Imports and Exports and Synchem.

51. Since there is a two-stage transaction involved and the transactions are through two affiliated intermediates the export price needs to be constructed on the basis of sales of Synchem to unaffiliated Indian customers and after applying adjustments for direct selling expenses and profit margins at each stage.

52. NHU has transferred \*\*\*\*\* Kgs of the subject goods to NHU Imports and Exports at RMB \*\*\*\*\* (US\$ \*\*\*\*\* at average exchange rate of RMB 8.26). NHU Imp & Exp has transferred the same quantity of the subject goods to Synchem at US\$ \*\*\*\*\* Transactions between NHU Imports and Exports and Synchem are FOB Ningbo port. Therefore, the transactions involve adjustments towards inland transportation from plant of NHU to port of loading and actual profit margin of NHU I&E as well as the credit cost involved.

53. Synchem has purchased \*\*\*\*\* Kgs of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/gm from NHU Imp & Exp at US\$\*\*\*\*\* and sold the same in Indian market at a gross invoice value of US\$ \*\*\*\*\* The sales of Synchem to Indian Customers are on CIF term and on DA/LC basis. Therefore, adjustments towards direct selling expenses, credit costs and profit margin of Synchem has been made to arrive at net export price at ex-factory level of NHU. Commission, overseas ocean freight and ocean insurance; and bank charges, as verified from the records of the company have been adjusted.

54. It is also noticed that VAT of 17% has been paid by the exporter on the net invoice value of NHU Imp & Exp and refund has been obtained @13% of this value. Therefore, the exporter has absorbed VAT of 4%, which is required to be adjusted to arrive at the net export price at ex-factory level. As far as profit of Synchem is concerned, records of Synchem show an overall profit margin of \*\*\*\*\*% on the subject goods during the POI. Therefore, in order to arrive at the net export price at NHU's factory level, an adjustment towards actual profit margin of the related exporter i.e., Synchem is also proposed to be made.

55. \* Accordingly, the net ex-works export price of NHU/Synchem works out as follows:

Product	Qty Kg	Net Invoice Value Synchem US\$	Total Adjustment NHU I&E	Total Adjustment Synchem	VAT Adjustment	Profit I&E **%	Profit Synchem **%	Net Value at NHU factory	Net Export Price US\$/Kg
1.7 MIU	****	****	****	****	****	****	****	****	****

## ii) Others

56. The export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined based on the lowest export price of the cooperating exporter. Accordingly, net ex-works export price for other non-cooperating exporters have been determined as US\$\*\*\*\* per Kg.

## c) Dumping Margins

57. On the basis of above normal value and export prices determined at the ex-works levels the dumping margins for exporters in China has been determined as follows:

Exporter	NV	EP	DM	DM %
China	US\$/Kg	US\$/Kg	US\$/Kg	
NHU/Synchem	****	****	****	48%
All others	****	****	****	70%

## F.2 Switzerland

58. The Authority notes that this exporter produces the subject goods and sells the same in the domestic market as well as in the European market and Indian market. However, during the POI only Vitamin-A Palmitate 1.7 BHA/BHT and 1.7 TOCO have been exported to India. The exporter has submitted that their sales in the home market being less than 2% of the total sale of the subject goods by the company are not representative sales for the purpose of Normal Value determination. It was also submitted by the exporter that more appropriate home market would be the EU, which represents around 60% of sales during the POI. In this connection the Authority notes that footnote 2 of the Agreement provides that

*"Sales of the like product destined for consumption in the domestic market of the exporting country shall normally be considered a sufficient quantity for determination of the normal value if such sales constitutes 5% or more of the sales of the product under consideration to the importing member, provided that a lower ratio should be acceptable where evidence demonstrate that domestic sales at such lower ratio are nonetheless of sufficient magnitude to provide for a proper comparison"*

59. The Authority notes that the exporter sold \*\*\*\* Kg of Vitamin A palmitate 1.7 MIU/Gm and \*\*\*\* kgs of \*\*\*\*MIU/Gm in the home market during the POI against export of \*\*\*\* Kgs of 1.7 MIU/Gm to India during the same period. Therefore, home market sales of the like product constituted more than 5% of the sales to India. Such home market sales being in sufficient quantities as per the Agreement are therefore, required to be considered for the purpose of determination of Normal value and accordingly, the Authority has considered the same for determination of normal value in the exporting country.

60. The exporter, however, made a plea that if their home market sales are required to be considered for the purpose of determination of normal value due consideration has to be made towards the difference in sales quantities and level of trade as the domestic sales are in smaller quantities and to direct retail customers and therefore, not comparable with the export sales transactions. The exporter, vide letter dated 10<sup>th</sup> April 2007, was asked to quantify and demonstrate the level of trade adjustments and other factors that affect the price comparability as claimed by them for fair comparison. The exporter, vide its letter dated 24<sup>th</sup> April and 16<sup>th</sup> May 2007 provided certain information and arguments for quantification of the adjustments towards the factors affecting price comparability and direct selling expenses in respect of domestic sales on account of small quantity sales to direct customers in Switzerland.

61. The Authority notes that Rule 6(i) in Annexure I and Article 2.4 of the Agreement provide that *"due allowance shall be made in each case, on its merit, for differences which affect price comparability, including difference in conditions and terms of trade, taxation, level of trade, quantities, physical characteristics, and other differences which are also demonstrated to affect price comparability"*. In terms of the above provisions the claims of the exporter has been examined by the Authority as follows:

- a) The claim of the exporter on adjustments towards lower transaction volumes in domestic market has been examined. It has been claimed that the domestic sales are in small quantities and average quantity sold per transaction in the domestic market is 41 Kgs whereas average quantity per sale in the Indian market is about 416 Kg. It has been argued that the difference in order quantities affects the respective prices as they charge a minimum quantity surcharge on small order quantities. In support of this some export invoices with small quantities have been produced. However, no evidence of small order surcharge in domestic market has been provided. It has been further argued that the quantities have direct impact on the price and an adjustment has to be made for comparison purpose. Accordingly, the exporter has quantified the adjustment based on the

difference in unit price for sales transactions to India of quantity below 300 Kg and above 300 kg. However, these quantity difference and small quantity surcharges are with reference to the export sales and no evidence of such a variation in prices on account of quantities in the home market has been provided. Therefore, the Authority is of the view that such adjustment cannot be admitted.

- b) In addition to the adjustment towards quantities, the exporter has claimed level of trade adjustment on the grounds that the domestic sales are mostly to direct consumers, whereas the export sales to India are mostly to resellers, which also affects price comparability. It has been argued that the price to direct customers in Switzerland and European markets is generally higher by about 5 to 7% than the prices to resellers. In support of this claim they have produced the evidence of contemporary invoices of same products to direct customers and reseller in Swiss market, which indicates a difference of about 5% between these prices. It has been argued that this mark up is allowed to the reseller to take care of its expenses and profit. Usually, resellers or agent gets a commission; or a markup in its prices which takes into consideration its expenses and margins and a commission/margin of 3% to 5% is normal in the trade. Therefore, the Authority is of the view that an adjustment of 3% towards this may be justified.
- c) The exporter has also claimed adjustments towards direct selling expenses in the home market i.e., inland freight from the plant to warehouse and associated insurance, storage and handling expenses, freight from warehouse to customer and associated insurance expenses. As far as domestic freight from warehouse to domestic customers are concerned, the exporter has provided the evidence of actual cost incurred for delivery through DHL courier and accordingly, the revised freight cost has been worked out as US \*\*\*\*\* per Kg.

62. Accordingly, the Normal value in Switzerland at ex-works level for the product under consideration works out as follows:

Representative sales in Home Market	Qty in Kg	Price in Euro	Price in US\$	Exch Rate	Adjustments US\$/Kg	Normal Value US\$/Kg
VIT A PALM 1.7 BHA/BHT	****	****	****	****	****	****
VIT A PALM 1.7 TOCO	****	****	****	****	****	****

- b) Export Price and Dumping Margins
- i) DSM Nutritional products

63. DNP has reported \*\*\*\* Kgs of export sales of the subject goods to India during the POI covering Vitamin A Palmitate 1.7 BHA/BHT and 1.7 TOCO. The Authority notes that the products of DNP for sale to India generally go (via ship) from the Netherlands to Singapore before being sent on to India. It has been submitted by the exporter that the products concerned are handled by the DSM Nutritional Products regional office for Asia Pacific in Singapore. It is a trading organization with a warehouse and invoices and re-exports the products to India and other Asia Pacific countries. The exporter has submitted that prices provided in the questionnaire response is the final export price for the Indian customer and the pricing mechanism between the related companies, i.e., DNP Switzerland and DNP Singapore them is not relevant for this investigation.

64. The exporter has provided information for adjustments towards direct selling expenses on account of Inland Freight from the Sisseln site to Venlo, Netherlands (warehouse) and associated insurance expenses; storage and handling charges; overseas freight from Switzerland to Singapore and Singapore to India and associated insurance expenses; and shipping charges. No adjustment has been claimed on packing expenses as the same is included in the cost and there is no difference between the export packing and domestic packing. Accordingly, the net export price at ex-works level works out as follows:

Export Price to India	Qty in KG	Value EURO	Rate Euro/kg	Value US\$	Rate US\$/Kg	Adjustments US\$/KG	Net Price US\$/Kg
VIT A PALM 1.7 BHA/BHT	****	****	****	****	****	****	****
VIT A PALM 1.7 TOCO	****	****	****	****	****	****	****

65. On the basis of Normal value determined for Switzerland and net export price determined for DNP, dumping margin for this cooperating exporter has been assessed as follows:

	NV US\$/Kg	Qty Kg	EP US\$/Kg	Qty Kg	DM US\$/Kg	DM value
VIT A PALM 1.7 BHA/BHT	****	****	****	****	****	****
VIT A PALM	****	****	****	****	****	****

1.7 TOCO						
Weighted Average	****	****	****	****	****	****
					21%	

66. DSM, in its post disclosure submissions has argued that since the Indian law does not provide for a threshold limit for the domestic sales to be treated as in sufficient quantities for determination of normal value the Authority should not merely relied on the WTO Agreement in this respect and evaluated the matter on its own merit in view of the fact that the domestic sales in Switzerland was very small (less than 2%) compared to its total sales. It has also been argued that a particular market situation i.e., the sales in Switzerland have been made in very small quantities whereas sales for exports to India are in much larger quantities exists in Switzerland, which should have been taken into account for determination of normal value in Switzerland. Under the above circumstances appropriate market for determination of normal value is the European Union and not Switzerland. The exporter has also commented that the weighted average dumping margin should be worked out on the basis of weighted average normal value and weighted average export price.

67. Domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that argued that, without conducting the on-site verification, acceptance of the data and other claims made by DSM is unwarranted and unsubstantiated. Domestic industry has further argued that under the above circumstance dumping margin for the exporters from Switzerland, including DSM, should have been based on the best information available i.e. third country information (European Union) or constructed cost on the basis of price paid or payable in India duly adjusted as prescribed under the Rules.

68. In this connection the Authority notes that the sales in Swiss market were found to be in sufficient quantities in relation to the exports to India, (which constituted more than 20% of sales to India) and therefore, considered appropriate for comparison with the exports to India. However, the exporters claimed, certain adjustment on its home market prices towards certain factors that affected the price comparability and such adjustments, which could be demonstrated and justified by the exporter with evidence, have been accepted by the Authority. The claim for adjustment on account of a minimum quantity surcharge could not be demonstrated by the exporter with reference to domestic sales and therefore, has not been accepted. Therefore, the arguments of the exporter in this regard are not tenable. As far as the error in dumping margin calculation is concerned, Dumping Margin is determined as the weighted average of the intermediate dumping margins, determined at subtype levels (weighted on the export quantities of product subtypes). The dumping margin has been determined for the above exporter correctly on the above basis. Therefore, there is no need for any change of dumping margins.

69. As far as the arguments of the domestic industry is concerned, the Authority notes that the exporter concerned had submitted the information required for determination of its dumping margin and offered itself for verification. On the factual matrix of the case the Authority decided to accept the data, to the extent it was substantiated, without verification and accordingly, dumping margin has been determined on the basis of the home market sales of the company as explained earlier. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument of the domestic industry to determine the normal value of the Swiss exporters based on selling price in the EU market or on constructed cost plus profit basis.

## ii) Other exporters

70. Export price for other exporters has been determined based on the lowest export price of the cooperating exporter from Switzerland as best facts available after allowing for adjustments as per exporters data. The export price so determined has been compared with the normal value determined for Switzerland. Accordingly, export price and dumping margin for all other exporters from Switzerland works out as follows:

NV US\$/Kg	Lowest EP Euro/Kg	EP US\$/Kg	Adjustments US\$/Kg	Net EP US\$/Kg	DM US\$/Kg
84.420	****	****	****	****	****
					33%

## F.4 Dumping Margins: Summary

Product	Country	Exporter	Dumping Margin	Dumping Margin %
			US\$/KG	
Vitamin-A Palmitate	Switzerland	M/s DSM Nutritional Products	****	21%
	Switzerland	All Others	****	33%
	China	NHU with Synchem	****	48%
		All Others	****	70%

The dumping margins so determined are significant and above de minimis.

## G. INJURY DETERMINATION

### G.1 Views of the Exporters and other interested parties

#### G.1.1 DSM Nutritional Products Ltd. (DNP)

71. DNP, in its post preliminary finding submissions, has argued that the conditions of competition between the imported article from China and domestic articles are quite different from the competition between Swiss exports and domestic articles and therefore, cumulative assessment of injury is not justified in this case. It has been argued that While Swiss product has been there in the

Indian market since many year, Chinese products have entered the Indian market since 2003 and has increased by three fold since then. Whereas China exports have shown a surge in volumes, exports from Switzerland have been more or less steady and market share of Swiss product has significantly declined compared to the previous years. The prices of Chinese products are also at lower prices compared to Swiss prices indicating that the conditions of competition between these products in the Indian market are quite different and therefore, cumulative assessment of injury is not warranted.

72. DNP further argues that the data for the period for which ADD was in force on imports from EU and other countries should be excluded from the examination as the imposition of duties led to a sudden reduction in imports, creating a virtual monopoly for the domestic industry. Therefore, this temporary situation does not reflect a natural or potential decline in sales of the domestic industry. DNP further argues that the domestic industry hopes to earn extraordinary price in the home market to finance its losses in the exports and therefore, the analysis of domestic industry's export and domestic sales should not be separated. DNP further argues that its export price does not have any price undercutting or underselling effects on domestic industry's prices because of the fact that the maximum sale price of the subject goods in India are fixed by Drug Price Control Order of India. Domestic industry sales its product both to formulation manufacturers and resellers. Prices to resellers would be lower than the DPCO price so as to provide for the expenses and profit margins of the reseller. Therefore, DNP's landed value being close to DPCO price, there could be no price undercutting/underselling effect.

73. It has also been argued that the basics customs duty on the product under consideration have been more than halved (i.e., falling from 35% to 15%) during the last five years which has clearly made imported material progressively more competitive, despite the fact that DNP has not reduced its CIF price during this period, and is no indicator for either dumping, or material injury caused thereby. The Rupee has also appreciated from approximately Re 48 to less than 44 against the US dollar from 2001 until 2005. Both of these changes occurred as a result of Government policy and help to explain the preference for imported material. Therefore, there is no causal link between the Swiss exports and the injury allegedly suffered by the domestic industry.

74. In its post disclosure submission DSM has reiterated its arguments on injury and causal links. They have also submitted certain information regarding sales by one of their reseller/importer through the said importer to support their arguments made earlier. In this connection the Authority notes that importer/reseller of DSM did not file any questionnaire response or any information at appropriate time. Therefore, submission of certain information by the reseller on its selling price at this stage of the investigation cannot be taken on record. As far as the issue of DPCO price and its impact on the injury to the domestic industry is concerned, it has been adequately addressed in the causal link analysis in this finding.



### G.1.2 Views of NHU/Synchem

75. NHU/Synchem in their post preliminary findings submissions have argued that the Volume of imports has grown due to import liberalisation in India, declining tariffs, currency appreciation and due to increase in domestic demand in India, which has one of the World's fastest growing economies. It has also been argued that the poor exports remuneration of the Applicant indicated in the Petition itself has led to any loss of income or profits during the POI. It has been further argued that the domestic industry seeks a unreasonable rate of ROCE return of 26% and injury to the Applicant domestic industry is not evident as it has clearly not had any difficulty in raising capital as reflected, as per its public domain website, in its acquisitions spree in India and abroad from 2004-2006. It has also been argued by the Chinese exporters that the principal concern of Public Policy in India concerning the Subject Goods is to ensure that prices of the Subject Goods are reasonable and inexpensive and not the normal pharmaceutical industry profits to the producers in view of the critical importance of vitamin A for public health in India. In its post disclosure comments the exporter has reiterated its arguments on injury and causal link.

### G.1.3 DPCO Issue

76. The exporters from China PR and Switzerland, in their respective submissions have submitted that the Drug Price Control Order, 1995 of Government of India applies also imported formulations, and therefore, the domestic industry's submissions at the hearing stage that the price ceiling applies only in respect of the re-sale price in India by the Importer is misleading. It has been argued that the price ceiling fixed by DPCO applies to all sales of the subject goods in India and sets the final selling price to the ultimate user. Since the imports are mostly by traders/resellers who supply the goods to local customers/users the importer/trader must buy the product at a landed value that is less than the DPCO price ceiling to take care of his resale margin. For this reason alone fixing the NIP at the DPCO price ceiling as requested by the Applicants must necessarily lead to exclusion of the exporters from the Indian market and unlawful denial of market access since there will be no margin for importers profit and further transport/logistics costs in India prior to final point of sale and after addition of such profits/costs, as the case may be, the final re-sale price in India would necessarily be higher than the DPCO ceiling price and thus ineligible for sale in India. Hence, such market access by the concerned exporters is possible only when the NIP at highest (if not lower still) is lower than the DPCO Ceiling price with sufficient margin left for importers (and any further distribution channels used by the importer prior to final point of sale to the customers) profits and transport/logistics costs within India.

## G.2 Examination by the Authority:

77. The Authority notes the views expressed by the interested parties in respect of the injury claims of the domestic industry and proceeds to examine the issues raised and injury claims of the domestic industry s follows:

### **G.2.1 Cumulative assessment of injury**

78. The Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules requires that where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that

- I) the imports from individual countries are above de minimis or cumulatively account for more than 7% of imports;
- II) the dumping margin against individual countries are above 2%; and
- III) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

79. DNP has argued that since the prices of the subject goods exported by them is significantly different from the price at which goods are being imported from China PR there is a lack of competition between these two products and hence they cannot be cumulated for assessment of injury to the domestic industry. In this connection it is noted that the dumped imports of the subject goods were entering the Indian market simultaneously from the subject countries during the POI. Though there was no export of the subject goods from China till 2003, both the countries have exported comparable quantities during the POI and margins of dumping of subject goods from each of the subject countries are more than the de minimis limit. The domestic products and products supplied by producers in the subject countries are like articles and are being used interchangeably. Transaction wise information on imports from various countries shows that the imports are being made by actual users in the Pharmaceutical industry, as well as traders who have imported the material for reselling to pharmaceutical as well as other user industries. Goods supplied by the countries involved are entering the Indian markets through the similar channels of distributions, during the same period through comparable sales channels and under similar commercial conditions. The domestic producer and exporters in the subject countries are selling the product to the same category of consumers. Imports from the subject countries are significantly undercutting and underselling the prices of the domestic industry in the market. Therefore, the products manufactured by the domestic industry and that exported by Chinese exporters and Swiss exporters are directly competing amongst themselves in the same market. In view of the above, the arguments of DNP cannot be accepted for decumulated injury assessment. Accordingly, the Authority holds that cumulative assessment of injury is appropriate in this case.

### **G.3 Examination of Injury and Causal Links**

80. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price

undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

81. Since Vitamin A Palmitates of various strengths have the same end use, the present investigations shall cover the subject goods in all its strengths and forms. Accordingly, overall condition of the industry and effects of the imports on the Vitamin-A business of domestic industry has been examined to the extent relevant.

82. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above such as production, capacity utilization, sales volume etc. have been examined in this section.

### **G.3.1 Volume Effects of Dumped Imports: Import volumes and market shares**

#### **a) Import Volumes**

83. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

84. The applicant has submitted the import data compiled from IBIS data source which shows that Imports have taken place from several sources including the subject countries during the injury investigation period. DGCIS transaction-wise import data has also been obtained for examination. However, examination of DGCIS data as well as the import data reported by the cooperating exports indicates that the DGCIS has underreported the import data of the POI to a very large extent. The cooperating exporters have reported significantly higher quantities of exports during the POI compared to import reported by DGCIS. Therefore, for the purpose of analysis of import volumes and its impact on the domestic industry the import volumes have been worked out after adjusting the DGCIS data for the imports reported by the cooperating exporters. Accordingly, the import volumes of subject goods are as follows:

Qty in Kgs						
COUNTRY	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	POI	POI Annualized
SWITZERLAND	2197	2370	1200	1560	11240.7	7494
Trend	100	108	55	71	511	341
CHINA	0	0	2005	1750	9900	6600
Trend	0	0	100	87	493	329

Total Subject Countries	2197	2370	3205	3310	21140.7	14094
Trend	100	108	146	151	962	642
OTHERS	8096	1549	458	25	1315	877
Trend	100	19	6	0	16	11
TOTAL	10293	3919	3663	3335	22456	14970
Trend	100	38	36	32	218	145

85. The above data indicates that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased substantially during the injury examination period, particularly during the POI. Imports from Switzerland have increased after decline upto 2003-04. Import from China has started only in 2003-04 and has increased significantly thereafter. The growth in import volume from the subject countries is significantly higher than the growth in total imports. It also shows that there is a quantum jump in dumped imports during the POI compared to the previous years.

**b) Actual and potential effects on capacity, output and capacity utilization of the domestic industry**

86. The performance of the domestic industry has been examined with reference to its capacity, output and capacity utilization and impact of the dumped imports on these parameters, if any.

87. The domestic industry has indicated that their total installed capacity for the liquid plant, where the subject goods is manufactured, is 110 MT per annum, on single shift basis. However, the plant is available for three shifts operation and accordingly, available capacity is 330MT per annum. Against this capacity the plant is used for about 67%. It is noted that this installed capacity is not dedicated for the product under consideration and in this plant the company manufactures about 35 different products. Production of individual product varies from year to year depending upon the demand. Therefore, the capacity of the producer has been assessed based on three shift operation for which the plant is actually available and total output of various products from the plant, including the product under consideration. Accordingly, the capacity and capacity utilization has been worked out as follows:

Year	Installed capacity (KG)	Production (All Products) (Kg)	Indexed
			Capacity Utilization (%)
2000-01	100	100	47%
2001-02	100	72	33%
2002-03	100	104	48%
2003-04	100	119	55%
2004-05	100	122	57%
POI Annualized	100	144	67%

88. The above examination shows that annualized production and capacity utilization of the liquid plant during the period of investigation is the highest in the last four years including the period of investigation. Therefore, capacity utilization

does not appear to indicate any deterioration of the performance of the domestic industry taking into account total out put of the liquid plant.

89. However, production of Vitamin A Palmitate by the domestic industry has been examined as follows:

	Qty in Kgs				
Production Vitamin A	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized
production for domestic market	****	****	****	****	****
Trend	100	135	158	96	126
Production for exports	****	****	****	****	****
Total production	****	****	****	****	****
Trend	100	135	173	182	212

90. The data shows that while total production of the subject goods by the domestic industry shows a steady growth the production for the domestic market has dropped significantly after showing a healthy growth till 2003-04, whereas the export by the domestic industry has grown significantly in the same period.

b) Actual and potential effect on sales and market share of the domestic industry:

91. The volume of domestic sales and effects of dumped imports on the domestic sales have been examined in terms of absolute sales of the domestic industry, demands and market shares:

	Qty in Kgs				
Sales	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized
Domestic sales	****	****	****	****	****
Trend	100	234	233	106	166
captive consumption	****	****	****	****	****
Trend	100	57	118	90	100
DI Sales including Captive consumptions	****	****	****	****	****
Trend	100	128	164	97	127

92. The above data shows that domestic sales and total sales of the domestic industry, after increasing significantly upto 2003-04, has declined significantly. The exporters have argued that the recovery of the production and sales till 2003-04 was due to the duty in force against EU, Georgia and Singapore and decline thereafter was bound to happen due to competition from several sources after removal of antidumping duty on these countries. The Authority notes that the antidumping duty was earlier imposed to neutralize the effects of dumped imports from certain countries and it had its desired result in terms of recovery of the domestic industry. However, decline in the production and sales from 2004-05 coincides with significant increase in dumped imports from China and Switzerland as shown in the previous section whereas the imports from the

countries against which duty was in force earlier has not increased even after revocation of duty. Therefore, the arguments of the exporters are not valid.

93. Demand and market share of the subject goods have been examined taking into account the domestic sales of the product and revised import volumes as noted earlier.

Qty in kgs

Demand Vitamin A	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized
DI Sales including Captive consumptions	****	****	****	****	****
Trend	100	128	164	97	127
TOTAL Imports	****	****	****	****	****
Trend	100	38	36	32	145
Total Domestic Demand	****	****	****	****	****
Trend	100	96	119	74	133

94. The above data shows that while the demand for the subject goods show a steady increase of about 33%, the sales of the domestic industry, after significant increase upto 2003-04, declined significantly. The imports from the subject countries have increased by over 500% while total imports have increased by only 145%. The dumped imports from the subject countries account for 94% of the total imports to India.

95. The market share of the domestic industry and dumped imports have also been examined as follows:

Market shares	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized
Domestic Industry	100	133	138	131	95
Switzerland	100	112	46	96	256
China	0	0	100	87	494
Other countries	100	20	5	0	8

96. The Authority notes that antidumping duty was in force on the subject goods imported from the European Union and other countries upto 2003-04. The Authority also notes that dumped imports from China PR has started entering the Indian market in significant quantities from 2004-05. Data shows that market share of the dumped imports from the subject countries have increased significantly whereas the market share of the domestic industry has declined after recovery during the intervening period.

97. The above analysis shows that the dumped imports from the subject countries have increased in absolute term as also in relation to imports into India, production in India and consumption in India. It is also seen that the volume of imports have increased more than the increase in demand. In other words, rate of increase of imports was more than rate of increase of demand.

### G.3.2 Price effect of dumped imports

98. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

#### a) Price undercutting and Price underselling

99. The net sales realization of the domestic industry has been determined considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts & commissions and freight & transportation. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The net sales realization of the domestic industry was compared with the landed value of the dumped imports to examine whether the dumped imports have significant price undercutting effect on the domestic industry.

100. For the purpose of price underselling analysis the non-injurious price of the domestic industry has been determined taking in to account verified cost and SGA expenses of the industry with a reasonable profit margin. The landed value of dumped imports was also compared with the non-injurious prices of the subject goods to determine the price underselling effect of the dumped imports as follows:

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	
Cost to Make and Sale	*****	*****	*****	*****	*****	
Trend	100	83	78	101	89	
Net Sales Realization	*****	*****	*****	*****	*****	
Trend	100	104	92	85	85	
Landed values						
SWITZERLAND	4014.15	3982.98	3889.60	3842.42	3812.81	
CHINA	0.00	0.00	3402.25	3284.27	3535.91	
Subject countries	4014.15	3982.98	3584.72	3547.32	3561.07	
Price Undercutting						
SWITZERLAND	*****	*****	*****	*****	*****	5-15%
CHINA	*****	*****	*****	*****	*****	10-20%
Subject countries	*****	*****	*****	*****	*****	10-20%
NIP					*****	
Price Underselling					*****	
SWITZERLAND					*****	10-20%
CHINA					*****	15-25%
Subject countries					*****	15-25%

101. The above data indicates that landed price of imports from the subject countries have been significantly below the net sales realization and non-

injurious price of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting and price underselling.

**b) Price suppression and depression**

102. To examine the price suppression effect of the dumped imports on the domestic prices the trend of net sale realization of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data indicates that though there is a decline in the cost of production of the subject goods during the injury investigation period, the fall in sales realization has been significantly higher than the decline in cost of production. The Authority notes that the product is subject to price control and therefore, the domestic industry has been prevented to increase its prices to recover the full cost. However, it also appears that the price effect of the dumped imports have kept pressure on the domestic industry and forced it to keep its prices lower in order to retain its market share.

103. The above analysis shows that the dumped imports have adverse volume and price effect on the domestic industry in terms of increase in volume of dumped imports both in absolute terms and market shares and by depressing the prices of the domestic market and eroding its market share.

**G.3.3 Examination of other injury factors**

104. Some of the injury factors i.e. actual and potential decline capacity, production, capacity utilization, sales and market shares; were examined in the previous section along with actual and potential increase in volume of imports and it was noted that

- a) Production and sales of the domestic industry for the domestic market has decreased over the injury period after showing significant increase upto 2003-04 in spite of the increase in the demand of the subject goods in the domestic market. The domestic industry has been prevented from increasing the production to the extent it could, in spite of good demand in the domestic market.
- b) While the Domestic Industry has the capacity to produce and sell the subject goods in the domestic market, the domestic industry has not been able to utilize the capacities adequately.
- c) Sales of the domestic industry decreased substantially after healthy growth upto 2003-04, which also resulted in declining the market share of the domestic industry. The domestic industry has not benefited from the increase in demand.

**a) Actual and potential effects on Profits**

105. Profits earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market were as follows:-



Year	Cost to make & sell Per MT (Rs.)	Selling Price / MT (Rs.)	Profit / (Loss) per MT (Rs.)
2001-2002	100	100	(100)
2002-2003	83	104	247
2003-2004	65	92	145
2004-2005	65	85	(352)
POI (Annualized)	58	85	(155)

106. It is seen that the Domestic Industry has made significant losses in its domestic sales and has moved to a situation of financial losses from a situation of profits, as is clear from the decline in production and sales volumes of the domestic industry over this period.

**b) Actual and potential effects on Employment and wages**

107. As far as Employment and wages are concerned there is no significant drop in employment level as indicator of injury to the domestic industry. However, the Authority notes that the domestic industry produces several products in the same plant and there is no dedicated employee strength for the product under consideration. Overall employment and wage scenario of the company shows that number of employees has declined whereas the expenses on wages have significantly increased.

Year	No. of Employees	Wages (in Lakhs)
2001-2002	100	100
2002-2003	100	31
2003-2004	99	37
2004-2005	95	44
Period of Investigation (Annualized)	93	45

**c) Actual and potential effect on productivity**

108. The labour productivity with reference to the total liquid production of the unit shows that the productivity has significantly improved.

Year	Total Production (All liquids) KG	No of employees	Productivity Kg
2001-02	****	100	100
2002-03	****	100	145
2003-04	****	99	168
2004-05	****	95	178
POI Annualized	****	93	216

109. However, the improvement in productivity has not translated into profitability for the domestic industry. It is found that even when productivity of the domestic industry significantly improved, which helped in reduction in unit cost of production, profits of the domestic industry significantly declined from a situation of profits to losses due to decline in selling prices.

**d) Actual and potential effects on Cash flow and Return on Capital Employed**

<b>Vitamin-A Palmitate</b>	<b>2001-02</b>	<b>2002-03</b>	<b>2003-04</b>	<b>2004-05</b>	<b>POI Annualized</b>
<b>Profit on domestic sales</b>	(****)	****	****	(****)	(****)
<b>Trend</b>	(100)	646	372	(494)	(754)
<b>Cash Profit local Production</b>	****	****	****	****	****
<b>Cash Profit per MT for Local - Rs</b>	****	****	****	****	****
<b>Capital Employed (In Lacs)</b>	****	****	****	****	****
<b>Trend</b>	100	212	248	280	322
<b>Return on Capital Employed (%)</b>	(****)	****	****	(****)	(****)
<b>Trend</b>	(100)	305	93	(741)	(698)

110. The above data shows that the cash flow and the return on capital employed have deteriorated after significant improvement in the intervening period.

**e) Inventories**

111. Examination of the stock position of the domestic industry shows that the stocks of the Domestic Industry have increased at the close of the Period of Investigation in spite of increase in captive consumption and export sales.

<b>Year</b>	<b>Opening Stock MT</b>	<b>Closing Stock MT</b>
2001-2002	100	100
2002-2003	0	13900
2003-2004	13900	2100
2004-2005	2100	300
<b>POI Annualized</b>	<b>300</b>	<b>2200</b>

## **Growth**

112. The Authority notes that though there is a healthy growth in demand the performance of the domestic industry in terms of parameters, such as production, sales, market share, profits, cash flow and return on investments shows significant decline.

### **g) Ability to raise fresh investment**

113. The exporters have argued that the domestic industry has not faced any investment problem and is in fact in an acquisition spree. Therefore, their ability to raise fresh investment has not been affected. However, the Authority notes that the domestic industry has not made fresh investments in the subject goods in the period of investigation. The financial performance of the domestic industry has significantly eroded which may have adverse impact on its future ability to raise fresh investments.

### **h) Degree of dumping margin**

114. The Authority notes that dumping margins from the subject countries, as an indicator of injury, are found to be significant and above de minimis.

## **G.3.4 Overall assessment**

115. The above analysis of the factors shows that in spite of the good demand in the domestic market, improvement in productivity and reduction in its cost of production compared to the previous years, the industry suffers injury on account of decline in production, and sales; low net sales realization; higher inventory built up; negative or low return on investments and profits. The injury suffered is material and significant. Therefore, the arguments of the interested parties that the petitioner domestic industry does not suffer any material injury are not valid.

## **G.4. Causal link**

116. The Authority notes that interested parties have argued that the injury to the domestic industry, if any, has been caused by factors other than the imports from the subject countries. It has been argued that the price fixed under Drug Price Control Order is the ceiling price at which the imported goods can be sold in the domestic market. Therefore, their prices to Indian customers and the landed values of their exports are also guided by the DPCO price. The domestic industry is also selling its goods close to the DPCO price and injury, if any, suffered by the domestic industry on account of its higher cost cannot be attributed to the imports from the subject countries.

117. It has also been argued that DPCO price being the selling price to the ultimate customers their export price take care of reseller's margin. Therefore, the Authority should calculate the injury margin based on the DPCO price and not on the basis of NIP if any, determined by the Authority.

118. In this connection the Authority notes that the landed value of the subject goods from the subject countries are significantly below the DPCO price as well as the selling price of the domestic industry even if a nominal margin for the reseller's margin is considered.

119. Existence of material injury and volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry in terms of its price undercutting, price underselling, price suppression, and depression effects have been confirmed in the previous section. However, before examining the issues of non-attribution raised by the interested parties, the mandatory factors have been examined as follows

- a) **Imports from Third Countries:** - Imports from countries not under investigation are either insignificant as some of them appear to be sample sales and not commercial sales or at prices higher than the import prices from the subject countries and therefore, do not affect the prices in the domestic industry. Dumped imports account for 94% of total imports during POI;
- b) **Contraction in Demand:** - Demand for the subject goods have increased substantially during the injury examination period. Therefore, possible contraction in demand cannot be attributed to the injury to the domestic industry.
- c) **Pattern of consumption:** - No significant change in the pattern of consumption has been alleged by any interested party.
- d) **Conditions of competition:** - The goods are freely importable. The petitioner is the major producer of the subject goods as the other viable producers have either stopped significant production or turned traders of the subject goods. Therefore, domestic competition could not be attributed to the injury to the domestic industry. No other evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has been brought to the knowledge of the Authority.
- e) **Developments in technology:-** There is no allegation of significant changes in technology which could have caused injury to the domestic industry. However, no cost disadvantage to the domestic industry due to technological difference has been claimed.
- f) **Export performance of the domestic industry:-**

Exports	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	April 2004 to September
In MT	-	-	****	****	****

The export sale of the domestic industry is substantial and shows significant growth. But the profitability from the export has been negative. The interested parties have argued that the export performance and lower price realization from its export sales have actually affected the domestic industry which cannot be ignored. However, the Authority notes that the performance of the domestic industry has been examined in relation to its domestic sales and the imports from the subject countries for the injury analysis purpose by segregating the prices and profitability in the domestic and export markets. Therefore, injury if any, caused due to the company's export performance has not been attributed to the dumped imports. Therefore, the arguments of the interested parties are not valid.

- g) **Productivity:** - Productivity of the domestic industry has improved in terms of total output and productivity per employee. Therefore, this cannot be attributed to the injury of the domestic industry.

120. As far as the arguments of the interested parties that injury caused to the domestic industry is on account of the Government's pricing and tax policies and has nothing to do with the dumped imports, the Authority notes that the landed value of the imports from the subject countries are much less than the DPCO price, even if a reasonable margin for the resellers is considered, indicating thereby that even if DPCO price is taken as the bench mark the dumped import have significant injurious effect on the domestic industry. Therefore, the arguments of the exporters that the Govt. Policies and DPCO prices are sole cause of injury are not valid.

#### **G.5 Factors establishing causal link**

121. Examination of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from subject countries. The dumped import prices and consequently the landed price of imports from the subject countries resulted in significant price undercutting and price underselling. Price under cutting has resulted in significant erosion in the market share of the domestic industry and reduction in absolute volume of sales of the domestic industry. It is also seen that though DPCO price has also prevented the domestic industry from increasing its prices to recover its cost of production, the price pressure of the dumped imports has prevented the domestic industry from increasing its sales volume and realizing its full capacity in spite of a very healthy demand situation in the domestic market.

122. The above non-attribution analysis shows that though there are other factors that could have affected the domestic industry, the dumped imports from the subject countries, through their volume and price effects, have caused significant injury to the domestic industry. The injury caused to the domestic

industry on account of such dumped imports from the subject countries is significant and material.

123. The above non-attribution analysis shows that though there are other factors that could have affected the domestic industry, the dumped imports from the subject countries, through their volume and price effects, have caused significant injury to the domestic industry.

124. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry suffers material injury and the injury has been caused by the dumped imports from the subject countries alongwith other factors discussed above. However, injury caused to the domestic industry on account of such dumped imports from the subject countries is significant and material.

#### **H. Magnitude of Injury and injury margin**

125. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry taking into account the cost of production and other associated costs of the domestic producer during the POI taking into account the principles laid down in the Supreme Court Judgment in Reliance Industries Vs Designated Authority which works out to Rs4301.03 per Kg of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/gm.

126. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has commented that NIP determination by the Authority is not in conformity with the books of accounts maintained by the Petitioners and the cost audit reports which have been duly certified and audited as mandated under the Drugs (Prices Control) Order, 1995 submitted to the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), the government organization formed under the aegis of the Ministry of Chemicals and Fertilizers. It has been argued that NPPA allows for a fair return of 26% as compared to 22% calculated by the Hon'ble Domestic Authority. These factors clearly bring down the Non injurious Prices. The domestic industry has further submitted that DPCO ceiling price level has been increased by NPPA during the investigation period based on the records submitted for the financial year 2005-2006 to Rs4564.50 per Kg. But the Non -Injurious Price fixed for the same period is much lower than the price level fixed by the NPPA.

127. The domestic industry further submits that as per the latest imports data for the period April to June 2007, the imports of the product concerned from China PR and Switzerland show that they have been adjusting the prices downwards and therefore are absorbing the preliminary duties. In order words, the prices of the subject goods from subject countries especially China PR is being further reduced as compared to the prices at which they were imported during the Period of Investigation. Clearly, the price effect is still being felt in the domestic Indian market, whereby the export price has now drastically reduced to absorb the Preliminary Duties and also as a consequence of the reduction of the Customs duty since the original Period of Investigation and due to the

strengthening of the India rupee, resulting into the price effect on the Domestic Industry being even worse.

128. The domestic industry has further argued that in view of the above, the duties should be recommended on the basis of the NIP worked out taking into account their cost data and not on the basis as calculated by the Designated Authority in the disclosure statement. However, if the Designated Authority rejects the higher NIP figures as submitted and adopts the DPCO pricing, it should take into consideration the revised DPCO figures which came into effect from 27.3.2007 based on the financial year data 2005-2006 which coincides with the Period of Investigation in the instant investigation.

129. The interested parties have argued that since DPCO price is the maximum price for sale in India this price should be taken into account for determination of injury if any caused to the domestic industry and injury caused to the domestic industry due to the DPCO price during the injury investigation period should not be attributed to the dumped imports. It has been further argued that the DPCO price being the maximum price for sales in India the comparison should take into account a margin for reseller's profit. In support of this some additional information of reseller has been produced by the interested parties after disclosure which could not be taken on record for the reasons stated earlier.

130. The Authority notes that the export transactions of these exporters are to direct customers as well as resellers. The importers have not provided any information about their reselling price and SGA expenses incurred or profit earned by them on such imports. Therefore, the Authority does not find any justification to make such allowance for the reseller's profit margin on the DPCO prices for comparison purpose and determination of injury margin.

131. The Authority also notes that in the instant case the NIP has been determined based on the data for the period of investigation as per the consistent practice of the Authority. The NIP has been determined as Rs4301.03 per Kg of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm. The current DPCO price fixed by NPPA is Rs4564.50 per Kg with effect from 27.03.2007, supposed to have been fixed on the basis of cost data for the period 2005-2006. There is a significant difference in the period for which data has been examined by the Authority, i.e., 18 months from 1<sup>st</sup> April 2004 to 30<sup>th</sup> September 2005, against 12 months data supposed to have been examined by NPPA for April 2005-March 2006. Further apparently, the rate of return adopted by NPPA and the Authority are different. Therefore, it would not be appropriate to adopt NPPA current price under DPCO for injury margin determination. By the same logic the NPPA price for the earlier period would also not be appropriate to determine the injury margin in this case. Therefore, the Authority has compared the NIP determined as above with the landed value of imports to work out the injury margins.

132. However, the Authority notes that during the injury investigation period the DPCO ceiling price had set the maximum price at which the domestic industry could have sold the goods in the domestic market. Therefore, as per the non-attribution standards, any injury, which could have been caused to the domestic industry due to this ceiling price, cannot be attributed to the dumped imports and the injury margin of the dumped imports needs to be restricted to the extent to which the dumped imports were below the DPCO price prevalent during the investigation period. Accordingly, the injury margin that can be attributed to the dumped imports work out as under:

Country	Exporter	NIP	LV	DPCO Price during POI	Injury Margin	Injury attributed to dumped imports	Injury attributed to dumped imports
		Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	%
Switzerland	DSM Nutritional Products	*****	*****	4125.9	*****	*****	5-15%
Switzerland	All Others	*****	*****	4125.9	*****	*****	15-25%
China PR	NHU with Synchem	*****	*****	4125.9	*****	*****	10-20%
China PR	All others	*****	*****	4125.9	*****	*****	25-35%

## I. Conclusions

133. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding the authority concludes that:

- i) The subject goods have entered the Indian market from the subject countries at prices less than their normal values in the domestic markets of the exporting countries;
- ii) The dumping margins of the subject goods imported from the subject countries/territories are substantial and above de minimis;
- iii) The domestic industry suffers material injury; And
- iv) The injury has been caused to the domestic industry both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries alongwith other factors.



**J. Indian industry's interest & other issues**

134. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

**K. Recommendations**

135. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having established positive dumping margin against the subject countries, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping and injury to the domestic industry. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

136. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties be imposed on all imports of the subject goods falling under chapter 28 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China PR and Japan, to be collected definitively from the date of imposition of the provisional duty. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Column No. 9 of the duty table annexed herewith.

137. Subject to the above the provisional findings, notified vide notification dated 23<sup>rd</sup> February 2007, are hereby confirmed

**L. Further Procedures**

138. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

139. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority

**Duty Table**

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	293621	Vitamin-A Palmitate	Any	Switzerland	Any	DSM Nutritional Products, AG Switzerland	DSM Nutritional Products Asia Pacific Pts Ltd, Singapore	313	KG	Rs
2	-Do-	-Do-	Any	Switzerland	Any other than China	Any other than above	Any	690	KG	Rs
3	-Do-	-Do-	Any	Any other than China	Switzerland			690	KG	Rs
4	-Do-	-Do-	Any	China PR	Any	Any Zhejiang NHU Company Ltd	Any Synchem International Company Ltd.	590	KG	Rs
5	-Do-	-Do-	Any	China PR	Any	Any other than above	Any	941	KG	Rs
6	-Do-	-Do-	Any	Any	China PR	Any	Any	941	KG	Rs